साप्ताहिक

पृथ्वी पर हम सब समय माया के यात्री हैं

समय माया

R.N.I. No.: MP/HIN/2006/20685

प्रधान संपादक- अजमेरा एस.पी. कुमार
B.COM., M.A., LLB, CAIIB, DLLLW&PM

Webite: www.samaymaya.com
Email: samaymaya@gmail.com
samaymaya@rediff.com

Cell: +91 7804872701, 9425125569
Phone Fax: +91 731 2015827

(C) All Copyrights reserved with chief editor, do not publish any matter without prior written permission

In case of any dispute, may be solved only in Indore Court Jurisdiction

वर्ष 08 अंक 23 प्रति सोमवार इंदौर, 6 से 12 जनवरी 2014 पृष्ठ 8 मूल्य 2/- रुपए

बलात्कारों में आड़ में, कांग्रेस कर रही जनहितों का बलात्कार

बलात्कार, धूर्त कांग्रेसियों का सत्ता चलाने, कुकर्मों से नजर हटाने का हथियार

हिन्दु संतों, न्यायाधीश पर आरोप लगाकर हिन्दुओं, न्यायिक व्यवस्था पर बना रही दबाव

भारत के केन्द्र की सत्ता को हांक रही कांग्रेस यथार्थ में शासक नहीं सफेद पोश सत्ता की शक्ति संपन्न घोर अपराधियों का गिरोह हैं, जिसका कार्य केवल येन-केन प्रकरेण जनहितों के नाम पर राष्ट्र की संपत्तियों को बेंच, गिरवीकर, अरबों करोड़ रु. का कमीशन डकारना है, उसके कुकर्मों पर जनता की नजर न पड़े, नजर पढ़ भी गई हैं, तो मीडिया टीबी चैनलों को टुकड़े डालकर तिल को ताड़, राई का पहाड़ बना कर आंखों के सामने खड़ा कर दो, ताकि जनता का भेजा फ्राई हो जाये, और वो इन कांग्रेसी गिद्धों की नोच खसोंट, कुकर्मों की तरफ आंख, कान और दिमाग न लगा सकें। राष्ट्र की 125 करोड़ जनता का और राष्ट्र को संयमित तरीके संचालित करने के लिये कानून और न्याय व्यवस्था व न्यायालयों का आम जन में जो विश्वास है, उसे तार-तार करने और बिखेरने में कांग्रेसी गंदे और नीच शूकरों की फौज ने उसके कुकर्मों, अपराधों पर जिला न्यायालयों से लेकर उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गये फैसलों और भविष्य में उसके विरूद्ध किसी भी निचली अदालतों, उच्च न्यायालयों या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा उसके विरूद्ध कोई टिप्पणी, फैसला न किया जावे या उसके लूट, खसोट, कमीशनखोरी देश और उसकी जनता को लूटने बेंचने या गिरवी करने के मामले में कांग्रेसी गिद्धों के अपराधों के बारे में सत्ताधीश श्वानों की इच्छा और उनके हितों को सर्वोपरि मान ही निर्णय देने का दबाव बनाने के लिये सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को 70 वर्ष से ज्यादा की उम्र में विधि प्रशिक्षु के बलात्कार का आरोप लगाकर यथार्थ में जस्टिस गांगुली को बलात्कार का अपराधी ही नहीं सिद्ध किया जा रहा वरन पूरे राष्ट्र की 125 करोड़ जनता के विश्वास, राष्ट्र की कानून व्यवस्था और वहां बैठे सत्ताधीशों जिन्होंने उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालयों में नियुक्तियां की है। सब के प्रति अविश्वास और जनता के साथ किया जा रहा छल प्रकट करता है। इसके विपरीत यथार्थ यह हैं, सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों द्वारा बड़ी हिम्मत करके, न्यायालयों की गरिमा का ध्यान रखकर, कांग्रेसी भ्रष्ट शूकरों द्वारा किये जा रहे घोटालों पर, कुकर्मों पर और सत्ता को अपने बाप की जागीर समझ लूटने-खसोटने के विरूद्ध पकड़े गये 0.001प्रश प्रकरणों पर निर्णय, प्रधानमंत्री मनमोहन और उनके सचितों जो भारत के श्रेष्ठ गुणी, ज्ञानी, जालसाज, धूर्तों द्वारा की जा रही बत्तमीजियों के विरूद्ध की गई टिप्पणियों से चिढ़कर पूरे कांग्रेस की चांडाल मंत्रियों की चौकड़ी,

(शेष पेज 7 पर)

करोड़ों को बेरोजगार बनाकर जीने योग्य बांटी जायेगी भीख

खा.सु. व मा. अधि. 06 से करोड़ों खाद्य विक्रेताओं किसानों को करेंगे बेरोजगार

सत्ता संभालते ही रु. 1 प्रतिकिलो गेहूं, चावल, बहुराष्ट्रीय डकैतों की लूट का षड़यंत्र, सरकारें कठपुतली

खाद्य सुरक्षा मानक अधि. 06 को लागू करवाने में वालमार्ट ने 550 करोड़ अमेरिकी डॉलर खर्च किया था, जो भारतीय रुपये में रु. 33000 करोड़ होते है। इसके बराबर ही धन भारत में रिलायंस आईटीसी की ब्रिटीश कंपनी की भारतीय कं. है। हिन्दुस्तान लीवर युनी लीवर का भारतीय संस्करण है, जिसमें 71 प्रतिशत साझेदारी है। टाटा, बिरला आदि ने भी लगभग रु. 70000 करोड़ खर्च कर जिसमें भारतीय संसद के 542 सांसदों को लगभग रु. 200 करोड़ प्रत्येक को बांटा गया, यह कानून इसीलिये बनवाया गया। ताकि 125 करोड़ से ज्यादा की आबादी के इस देश के खेतों से लेकर उनके पेट भरने के लिये मुंह तक पहुंचने वाली हर खाद्य वस्तु पर कब्जा कर उसके दोगुनी से लेकर 100 गुनी कीमत पर बेच कर देश को लूटा जा सके, जिसमें देश की धरती पर पैदा किया हुआ खाद्यान्न पर इन गिद्ध बहुराष्ट्रीय कं. को पूर्ण काननूी अधिकार के साथ निचोड़ कर अमेरिकी इंगलैंड की अर्थव्यस्थायें चलाई जाये, इसलिये खाद्य सुरक्षा और मानक अधि. 06 को संसद, राज्यसभा में कब पास करके कब राष्ट्रपति ने मुहर लगा दी जनता और मीडिया को कानों कान खबर भी न हो सकी, वालमार्ट की भारतीय संसद में लाविंग करने और 550 करोड़ अरब डॉलर की पोल खुलने से मालूम पड़ा कि भारत में इन विदेशी कं. को प्रवेश करवाने और रिटेल विपणन गतिविधियों के लिये कांग्रेस क्यों उतावली हुई जा रही थी। आईटीसी, हिन्दुस्तान लीवर, रिलायंस, केडबरीज, पारले आदि ने भी रु. 10,000 करोड़ खर्च कर पूरा कानून ही आसानी से पास करवा लिया। इसकी जानकारी जब समय माया को सन 2006 में लगी और इसका अध्ययन कर सबसे पहले प्रकाशित किया कि

(शेष पेज 3 पर)

रूस की गोदी में 20 वर्ष से सड़ रहे, विमान वाहक से राष्ट्र की रक्षा का दंभ

क्या विक्रमादित्य पर रु.10000 करोड़ हुआ हजम

कुल 20000 करोड़ में 66 वर्ष में भी हम अपना रक्षा उत्पादन नहीं कर सके, मात्र कमीशनखोरी के कारण

भारतीय नौ सेना में हाल ही में शामिल किये गये भारतीय जल पोत विक्रमादित्य पर भारत सरकार भले ही राष्ट्र की रक्षा का दंभ भरे, पर उसका यथार्थ यह है कि रूस की नौसेना ने इस जहाज जिसे गोर्शकोब के नाम से जाना जाता था, 30 वर्ष से ज्यादा उपयोग कर इसे अनुपयोगी मान रूस की क्षीर गोदी में 1986 से ही पटक रखा था, स्वाभाविक ही था सन 1986 से निष्क्रिय पड़े इस विमान वाहक पोल की 20 वर्षों में और खराबी आई ही होगी जिस अटल सरकार ने इसे 1 रु. में खरीदकर पुन्नवीनीकरण सौदा रूस सरकार से किया था, कांग्रेस सरकार के आते ही पहले रुपए 6000 करोड़ में सौदा किया गया। अर्थात रु.5000 करोड़ डकाले गए। फिर उस पर पुर्ननविनीकरण का खर्च बढ़ते-बढ़ते रु.15000 करोड़ से ज्यादा का कर दिया गया, स्वाभाविक था रक्षा मंत्री के एंटोनी, सोनिया और मनमोहन ने मोटा कमीशन भारत की जल सेना की आवश्यकता बताकर डकारा गया और बदले में 1960-65 का रूसी विमान वाहक पोत का संस्करण खरीदा गया, क्योंकि भारत की जल सेना में एक भी बड़ा विमान वाहक पोत भी जल सेना पोत विक्रांत सेवा निवृत्ति के बाद नहीं था। जबकि राष्ट्र की आजादी के बाद से हमारे सत्ताधीशों की कमीशनखोरी और लूट की नियत देश में ठोस और लंबी अपने रक्षा उत्पादनों की कोशिश ही नहीं की, अन्यथा हम हमारे चिर शत्रु चीन से हथियारों के मामले में भले ही आगे नहीं तो लगभग बराबरी पर हो तो, पर हमारे सत्ताधीशों ने अपनी नीच कमीशन खोरी की मानसिकता के चलते ऐसा नहीं होने दिया जबकि अंग्रेजों द्वारा छोड़ी व्यवस्था में पूरे भारत में 39 फैक्ट्रिया, मुम्बई, कोचीन, कलकत्ता के शिप यार्ड थे,

(शेष पेज 6 पर)

कांग्रेस के एजेंट अन्ना, आप का केजरीवाल, सब बहुराष्ट्रीय कंपनियों की कठपुतली

लोकपाल नहीं जोकपाल-कभी किसी को नहीं मिलेगी सजा-बर्बादी जनता की

सारे नेता बहुराष्ट्रीय कं. के पाले श्वान, भारी भ्रष्ट, जालसाजों अंबानी, टाटा बिरला, आईटीसी, मित्तल, हिन्दुस्तान लीवर आदि के लिये बनाये, देश की गुलामी के कानून- मरेगी जनता

राष्ट्र की सत्ता में बैठी कांग्रेस, संपग्र गिरोह और पूरे देश के सासंदों ने मिलकर आंख भींचकर लोकपाल बिल पास कर दिया, मात्र सपा ने विरोध किया जबकि इस लोकपाल बिल के पास करवाने भ्रष्ट नेताओं और अधिकारियों को घेरने और जेल पहुंचाने की जिस इच्छा से ये कानून बनवाया गया यथार्थ में इस कानून में कोई शिकायतकर्ता, शिकायत करने से पूर्व ही सारे दस्तावेज और साक्ष्य इकट्ठे करेगा फिर शिकायत करेगा। पहले तो मुश्किल से ही वो नेता अधिकारी प्रकरण पंजीकृत होने देगा। थानों की पुलिस उसे हड़कायेगी, डरायेगी, धमकायेगी, फिर भी न्यायालय में प्रकरण पंजीकृत हो भी गया तो भी धन, बल, छल, प्रपंचों से उसके दस्तावेजों, साक्ष्यों को झूठा सिद्ध करवा कर, झूठी शिकायत सिद्ध करवा कर उस शिकायतकर्ता को ही अंदर कर दिया जायेगा वह भी 3,6 माह या एक वर्ष, दो वर्ष नहीं, पूरे 5 वर्ष के लिये ताकि फिर वह शिकायत करने लायक ही न बचा रहे और जेल में ही उसे नेता अधिकारियों के इशारे पर कुटवा -पिटवा कर खत्म करवा देगा। इसी कारण सभी पक्ष-विपक्ष भाजपाई धुरंधर विशेषज्ञ नेताओं ने इस तकनीकी चालाकी और अपनी सुरक्षा के इस लोकपाल बिल में पूर्ण व्यवस्था होने के कारण बिना किसी रूकावट और बहस के सफल बनाने में थोड़ी सी भी देर नहीं लगाई। अन्ना ने हर आंदोलन में कांग्रेस को भरपूर फायदा पहुंचाया, जब-जब उसने आंदोलन, अनशन कर रामलीला मैदान घेरा, तब-तब मीडिया ने उसे कांग्रेस के इशारे पर ही पूरा सहयोग कर पूरे देश के टीवी चैनलों पर अनवरत उसी को प्रस्तुति देते रहे, इस के पीछे, कांग्रेस ने अपने कोल घोटाले, 2-3जी घोटालों पर से ध्यान हटाकर अपनी बदनामी बचाई और मामलों की लीपा-पोती करती रही। इसी लोकपाल बिल के आंदोलन को अन्ना ने 15 जुलाई 11 से शुरू किया और 23 जुलाई 11 को स्थगित कर घोषणा कर दी कि 16 अगस्त 11 से आंदोलन फिर किया जायेगा कांग्रेस ने मीडिया को धन से अप्रत्यक्ष सहयोग देकर मीडिया को अन्ना को घेरे रखने का इशारा कर 5 अगस्त 11 से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-06 को लागू कर दिया और जनता को कानों कान खबर नहीं होने दिया। जिसकी तैयारी बहुराष्ट्रीय कं. 1985 से कर रही थी। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधि. 06 में वॉलमार्ट, रिलायंस, टाटा,ब्रिटिश कंपनी हिन्दुस्तान लीवर और इंडियन टोबेको कं. बिरला,

(शेष पेज 2 पर)

साप्ताहिक समय माया

संपादकीय

भारतीय लोकतंत्र में आती जागरूकता

हाल ही में राष्ट्र के 5 राज्यों में हुये चुनावों ने राजनैतिक दलों को जनता ने अपने मतदान कर जिन्हें चुना खास कर दिल्ली में, जहां राजनीति के जाने-माने चेहरों को नेपथ्य में भेजा गया वहीं दूसरी और भ्रष्टाचार के विरोध में हुये आंदोलन से उपजे आम आदमी की पार्टी को, जिसका हिस्सा इतिहास मात्र 10-12 माह पुराना भी नहीं था, इसके विपरित उनकी भ्रष्टाचार के विरूद्ध लड़ने की दृढ इच्छा शक्ति के सामने जनता ने नमस्तक हो अपना नेता चुन कर, बड़े-बड़े राजनैतिक धूर्त दिग्गजों को पटखनी दे दी, साथ ही 15 वर्ष से मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जैसी महिला को चिलाने पर मजबूर कर दिया कि हम महामूर्ख है या हम महाधूर्त है। जनता धूर्तता समझ गई और चलता कर दिया। दूसरी और मप्र व छत्तीसगढ़ में पुनः भाजपा के मुख्यमंत्रीयो के नाम पर जहां पार्टी को चुना वहीं दूसरी ओर उसी पार्टी के भ्रष्ट धूर्त मंत्रियों को भी धूल चटा दी, परन्तु दोनों ही प्रदेशों में भाजपा के आने का कारण यह नहीं था, कि दोनों मुख्यमंत्रियों ने बहुत अच्छा साफ सुथरा, भ्रष्टाचार हीन प्रशासन दिया था, वरन इनका प्रशासन भ्रष्टाचार तो था, परन्तु वह कांग्रेस की भ्रष्टाचार की हद तक खुली डकैती नहीं था, फिर दोनों ही प्रदेशों में कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्रियों दिग्गी दानव, अजीत जोगी की तरह चारों तरफ गिद्ध नोच के दिये हुये घावों को केन्द्र मनमोहन सरकार ने महंगाई, घोटालों से जो नमक छिड़ककर न केवल सूखाने भी नहीं दिया और जलन, पीढ़ा भी लगातार देने के कारण दोनों ही प्रदेशों की जनता ने कुये और खाइ में से खाई में वोट देकर कूदना ज्यादा पसंद किया, जहां कम से कम जिंदगी जीने और जान बचने की संभावना है। दोनों ही प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों पर भ्रष्टाचार के दाग ज्यादा गहरे नहीं थे, जबकि पूर्व के कांग्रेसी मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार, लूट और डकैती में परास्नातक बनने की होड़ लगा रहे थे, जनता बिजली के लिये चिल्लाती थी तो ये कांग्रेसी मुख्यमंत्री सार्वजनिक मंचों से अपने भाषणों में उल्टे ही जनता को नसीहत देने लगते थे कि बिजली नहीं है, तो अंधेरे में रहना सीखो, सड़के नहीं थी या गड्ढों से भरी हुई थी उस पर जनता को नसीहत दी जाती थी, कि सड़के नहीं है तो गड्ढों में चलना सीखों, इसलिये दोनों प्रदेशों की जनता ने कांग्रेसियों को घास नहीं डाली। इसके लिए विपरित दोनों ही प्रदेशों में जनता के पास यदि आम आदमी पार्टी की तरह विकल्प होता तो मप्र और छत्तीसगढ़ में भी आप दिल्ली की तरह भाजपा और आप में ही कड़ा मुकाबला करवा देती। दोनों ही प्रदेशों में डकैतों और चोरों में से चोरों को चुनना मजबूरी थी। राष्ट्र की राजधानी दिल्ली जैसे महत्वपूर्ण स्थान पर धन,बल, छल, उन्मुक्त और इतिहास हीन लोगों को मात्र ठोस विचारधारा के आधार पर तीसरे विकल्प के रूप में चुन कर जनता ने यह सिद्ध कर दिया की सत्तायें चलाने के लिए ठोस विचारधारा, जनहित की सोच होना धन, बल, छल, उन्मुक्त और इतिहास होने से ज्यादा जरूरी है, जनता के धन,बल, छल से ज्यादा लंबे समय तक छला जाना और सत्ता में आना फिर भ्रष्टाचार कर उन्हें लूटना, जनता के देश के भविष्य के लिये ठीक नहीं, मौका मिलते ही जनता उन्हें धूल चटा सकती है। यथार्थ में लोकतंत्र में होना भी यही चाहिये कि जिनके पास ठोस और श्रेष्ठ जन हितकारी विचार ही नहीं है। उन्हें सत्ता में बैठाया या चुना ही नहीं जाना चाहिये, क्योंकि जो भी दल और उसके नेता धन, बल और छल से चुनकर आयेंगे वो उसी धन, बल और छल का प्रयोग सत्ता में बैठते ही स्वाहितों में कर जनता और राष्ट्र का भविष्य बर्बाद करेंगे। इसके विपरीत आप जैसी पार्टीया जो एक मात्र भ्रष्टाचार दूर करने, 700 ली. पानी मुफ्त देने, बिजली की कीमतें आधी करने का वास्ता देकर सत्ता में आई है। यथार्थ में वे क्या और कैसे जनहित कर पायेगी या नहीं कर पायेगी यह तो भविष्य ही परिभाषित कर पायेगा। इसके विपरित कांग्रेस और भाजपा व अन्य सभी राजनीतिक दलों तथा नेशनल कांग्रेस, बसपा, सपा व अन्य सभी दल जो संसद में विराजे है, सभी ने बहुराष्ट्रीय कं. से, जो देशी विदेशी है। इतना मोटा धन डकार राष्ट्र के संसाधनों को ही उनके पास गिरवी कर दिया है, अधिकांश स्थानों पर बिजली उत्पादन का ठेका रिलायंस, टाटा को देकर मोटा धन डकारा और हर महीने रु. 2 से 5 प्रति यूनिट का अरबों रु. प्रतिदिन का कमीशन डकारने के लिये 80-90 पै. प्रति यूनिट उत्पादन लागत की बिजली को रु. 5,6,7, 8 प्रति युनिट में खरीदने के अगले 10 वर्ष तक के अनुबंध कर रखे है। जब खरीद ही महंगी है, तो आपूर्ति सस्ती कैसे की जायेगी। यह हाल कांग्रेस, भाजपा व अन्य सभी राजनीतिक सत्ताधीशों ने कर रखे है, ताकि उनकी सत्ता रहे न रहे। उन्हें मोटा कमीशन मिलता रहे। अर्थात भ्रष्टाचार दूर करने के लिये जड़ों से भ्रष्टाचार वृक्ष को काटने की जरूरत होगी। पर कमा बहुत खतरनाक है और भारी भी है, परन्तु असंभव नहीं। राष्ट्र कर राजधानी में जनता ने जिस विचारधारा को चुना है। परिवर्तन की कोशिश की है, जिसने बड़े-बड़े दिग्गजों को दिन में तारे दिखा दिये है। इससे संभावना भी आज नहीं नहीं तो कल पूरी होगी कि जिन पूंजीपतियों ने अपनी जालसाजियों से सत्ताधीशों को मोटा धन खिलाकर राष्ट्र के आधारभूत संसाधनों पर कब्जा जमा जनता को कैसे लूटा जा रहा है, सत्तायें बदलने पर इन पूंजीपतियों तथा रिलायंस, टाटा, बिरला, आईटीसी, हिन्दुस्तान लीवर में की जालसाजियों और लूट के लिये अंदर कर जनता को राहत पहुंचाई जा सके।

शास. अस्पतालों में सेवाओं की आउटसोर्सिंग से कमाई में करोड़ों का खेल

म.प्र. स्वा. विभाग में शास. धन की चारों ओर बंदरबांट

एनआरएचएम, आरसीएच, मलेरिया जैसे 84 विभाग का धन केवल कागजों पर खर्च

म.प्र. के स्वास्थ्य विभाग में आये दिन समाचार पत्रों में नये कारनामों और मरीजों की दुर्दशा अदने से वार्ड बॉय से लेकर संचालक स्वास्थ्य विभाग तक सब वसूली और लूट की कहानियां प्रकाशित होती रहती हैं। पर यहां के निकम्मे डॉक्टरों से लेकर डायरेक्टरों तक कोई को भी थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ता और वे नित नये अपनी बत्तमीजियों, कमीशनखोरी, निकम्मेपन, लूट, हरामखोरी, कामचोरी, गिद्धों की भांति मरीजों और शासन के धन को नोचने से लेकर मरीजों पर ड्रग ट्रायल से बच्चे बदलने मुर्दों की आंखें, दिल और जो भी अंग काम आ जायें निकालने तक के कार्यों में अपनी जादूगरी पूर्ण करिश्मे दिखाने में लगे रहते हैं। यहां तक की सेवा शर्तों में स्पष्टतः लिखा होने कि वे निजी व्यवसाय नहीं करेंगे, साथ ही वे इसका नॉन प्रोसेसिंग भत्ता भी प्राप्त करते हैं, इसके विपरीत इन जालसाज मानसिकता के डॉक्टरों पर शासन ने नकेल कसने की कोशिश की तो ये हरामखोर हड़ताल पर जाने की धमकी देकर ब्लेकमेल करने लगे अर्थात चोरी और सीनाजोरी। स्पष्ट करती है कि जिन्हें जनता भगवान के रूप में पूजती है, मानसिक रुप से कितने शैतान है। यथार्थ में ये शैतानियत पीएमटी के फर्जीवाड़े ने और स्पष्ट कर दी, यदि 1970-72 से शुरु हुए इस जालसाजी कांड को खोला जाये तो बहुत सारे नामी गिरामी डॉक्टरों की सच्चाई सामने आ जायेगी। जिसमें पुरानी कोचिंग संस्थानों ने यह खेल शुरू किया था, स्वाभाविक है कि जो इतनी जालसाजियों से डॉक्टर नहीं यथार्थ में शैतान ही बने हैं। जनता के स्वास्थ्य के नाम पर ये फर्जीवाड़ा विश्वव्यापी है, अमेरिका में में चल। शटडाउन इसी जन स्वास्थ्य का परिणाम ही है। यूरोप की कंपनियां आखिर क्या औषधि परीक्षण के लिये भारत की जनता का पशुओं से भी गया बीता मानकर उपयोग कर रही हैं। अगर उनमें मानवता होती तो शायद ये दुकृत्य करने का साहस ही नहीं जुटा पाती, परन्तु इसके विपरीत इतने सारे कुकर्मों की लंबी सूची के बाद भी अपने हर दुष्कर्म को सही ठहराने के लिये हड़ताल पर जाने से भी नहीं चूकते। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री से लेकर राज्य सरकारों के स्वा. मंत्रियों तक प्रधान सचिव, सचिव और संचालकों तक सभी लूटने में लगे रहते हैं। दवा खरीदी, मशीनों अस्पतालों के सामान की खरीदी जो अरबों रु. में होती है, ये 25 से 40 % करोड़ों रु. का कमीशन डकार जाते हैं। स्वास्थ्य विभाग में केंद्र और राज्य की कुल 84 योजनाओं में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को पैसा मिलता है, जिसमें से अधिकांश में जनता का स्वास्थ्य कागज के पलंगों पर, पेन और उसकी स्याही से आंकड़ों का स्वास्थ्य सुधारते रहते हैं। यथार्थ में मरीजों के भोजन, दवा व अन्य चिकित्सीय सामग्री के हर हिस्से में अस्पतालों के प्रबंधन में डॉक्टरों से लेकर वार्ड बाय तक लूट खसौट करते ही हैं। दवाइयां बेचने, कम खरीदने, समय बाधित, स्तरहीन खरीदने तक के सारे उच्च स्तर पर कमीशन डकारने जो कि 25 से लेकर 80-90 % तक हो करते हैं। दूसरी तरफ एक्सरे मशीन, सोनोग्राफी, डायलेसिस आदि अनेकों मशीनों से लेकर बिजली का सामान, पलंगों, स्ट्रेचर आदि तक में जानबूझकर तोड़फोड़ करने, खराब बिस्तरों, चादरों, कंबलों, पर्दों आदि को चुराकर ले जाने, जानबूझकर फाड़ने तक सब कुछ किया जाता हैं, ताकि नई खरीदी की जा सके। काम न करने, मरीजों को परेशान करने के बहाने मिल सकें, साथ ही एक्सरे, सोनोग्राफी, रक्तजांच व अन्य जांचों के लिये अपने कमीशन वाले व केन्द्रों पर भेज कर शासन का धन भी लुटायें। मरीजों और उनके परिजनों को लूटे, इस प्रकार सरकारी जिसमें प्रदेश के सभी मेडिकल काःलेजों, जिला चिकित्सालयों आदि में भी मरीजों की चिकित्सा के नाम पर भी आउटसोर्सिंग के नाम पर भी करोड़ों का खेल कर डॉक्टरों और अस्पताल प्रबंधन द्वारा धन हजम किया जा रहा है।

सूचना के अधिकार में इंदौर, उज्जैन, देवास के मु.चि.अ. से जानकारी मांगी गई, तीनों ही जालसाजों द्वारा जानकारी न देने के षड्यंत्र वहां के मु.चि.अ. और उनके धूर्त स्टॉफ द्वारा की गई। इंदौर के धूर्त, हरामखोर मु.चि.अ. डागरिया के स्टाफ ने मात्र रु. 40/- जमा करवाकर 20 पेजों की जानकारी जबकि कुल आवंटन जो 84 योजनाओं में जिसमें एनआरएचएम, आरसीएच, टीबी, पोलियो, मलेरिया, अंधत्व निवारण, कोढ़, जननी सुरक्षा आदि अनेकों योजनाओं में आता हैं। जिनके औषधियों, भोजन, देखरेख आदि के लगभग 84 मदों में धन के आवंटन की जानकारी मात्र 20 पेज जिसमें एनआरएचएम की जानकारी भर दी गई, मात्र अपील की गई संयुक्त संचालन डॉ. पंडित जो 20 से ज्यादा वर्षों से अजगर की तरह जमा हुआ हैं कि जानाकरी अधूरी दी गई। पर इस हरामकोर, जालसाज जो अपने भ्रष्टाचार और कुकर्मों के बारे में समाचार पत्र उसके विरुद्ध कुछ न छापे रु. 2 लाख से ज्यादा महीना बांटता है। अपने ही विभाग की जानकारी वह भी संपादक अजमेरा को कैसे दे दें, 8 जिलों के सीएमओ से लगभग रु. 8 से 16 करोड़ जिसमें 5 आदिवासी जिलों से रु. 2 से 3 करोड़ की वसूली करता है, जिलाधीश, संभागायुक्त, आयुक्त स्वा. सेवायें, मंत्री और मुख्यमंत्री तक इसके पेरोल पर होने के कारण ये मक्कार भ्रष्ट शूकर 20 से ज्यादा वर्षो से लूट मचाये हैं। डॉ. डागरिया रु. 5 करोड़ सरकारी योजनाओं से और रु. 10 करोड़ प्रतिवर्ष, नर्सिंग होम्स, ब्लड बैंकर्स, पैथोलेब्स, बच्चे पैदा करने की दुकानें दवा कंपनियों से वसूलता है। इसलिये इस श्वान को 3-4 सूचना के अधिकार में दिये आवेदनों का वहां बैठे हरामखोरों ने न तो बिन्दुवार समयावधिवार शुल्क मांगा, न जानकारी दी अपीलों को उस धूर्त पंडित ने उलझा दिया। यही हाल देवास के गिद्ध सीएमओ पूर्व विनार और वर्तमान में बैठा डॉ. गर्ग भी आने के साथ ही हरामखोरी पर उतर कर सभी योजनाओं में से लाखों रुपये का हिस्सा बटोर रहा है। उज्जैन में सीएमओ को बार-बार बदला जा रहा है, वहां अधिकांश स्टाफ न तो कभी सीटों पर मिलता है और न ही वहां भ्रष्ट श्वान कभी सूचना के अधिकार में जवाब देते हैं। स्वाभाविक था देवास और उज्जैन के सीएमओ विरुद्ध संयुक्त संचालक उज्जैन संभाग को अपीलें की गई वहां डॉ. नागर हैं, उसने भी दो महीने के बाद न तो अपीलों की सुनवाई की और न ही जानकारियां दिलवा पाये। ये डॉक्टर्स नहीं भ्रष्ट गिद्धों का टोला है, जिसे जनस्वास्थ्य से नहीं अपनी वसूली से और जेब के स्वास्थ्य सुधारने से मतलब रहता है।

लोकपाल नहीं जोकपाल-कभी किसी को नहीं मिलेगी सजा... पेज 1 का शेष

मित्तल व अन्य विदेशी कं. से मिले रु. डेढ़ लाख करोड़ की मोटी रकम को सभी सांसदों को लगभग रु. 200 करोड़ हर सांसद को बांटकर पास करवाया गया। वॉलमार्ट की भारत के रिटेल और खाद्य व्यवस्था में कब्जा करने की पोल खुली और तथ्य सामने आये कि उसने इस काम के लिये 550 करोड़ अरब डॉलर खर्च किये। जब इस खाद्य सुरक्षा मानक अधि. 06 को अध्ययन किया तो यह सच सामने आया कि इन देशी-विदेशी कं. के षड्यंत्र के तहत पूरे खाद्य व्यवसाय में लगे लगभग 5 करोड़ लोग जो सब्जी-भाजी के व्यवसाय से लेकर मध्यमवर्गीय देशी उद्योगों तक और लगभग 5 करोड़ कृषकों, कृषि कार्य से जुड़े खाद्य वस्तुओं के आड़तियों से लेकर गली-मोहल्ले की दुकानों तक सबको बेरोजगार कर दिया जायेगा। इसके लिये कांग्रेसी गिद्धों ने मौके का इंतजार किया। जैसे ही अन्ना के आंदोलन के सहारे 23.07.2011 को स्थगित आंदोलन की घोषणा 16.08.12 से करने के बीच में मिले समय में उसे 5 अगस्त 11 से लागू कर दिया गया, जब कांग्रेस पूर्ण आश्वस्त हो गई कि इसके विरोध में 5 करोड़ व्यापारी और 5 करोड़ किसान खड़े होकर आंदोलन नहीं करेंगे, फिर बाद में भी लोकपाल के लिये जब-जब आंदोलन किये सरकार ने कभी अपने घोटालों पर से तो कभी उसकी आड़ में पेट्रोल-डीजल की कीमतें बढ़ाई। अन्ना उकनी टीम के केजरीवाल व अन्य सभी ने भ्रष्टाचार की मूल जड़ में बैठे लाखों-करोड़ की संपत्तियों और उद्योगों के मालिकों रूपी डकैतों जो अपने स्वार्थों को सिद्ध करने के लिये कांग्रेस, भाजपा, सभी सत्ताओं, नेताओं को धन देकर या मोटी रिश्वत देकर खरीदकर राष्ट्र के संसाधनों का उपयोग करते है, जिसमें अंबानी, टाटा, बिरला, आइटीसी, केडबरीज, पारले, हिन्दुस्तान लीवर जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनी जो हर दिन जनता से हजारों करोड़ लूट रही है। उनके विरूद्ध अपने आंदोलन क्यों नहीं किये, उनका नाम लेने में उनके विरूद्ध आवाज उठाने में क्यों चुप रहे, जो देश की जनता को लूटने, गुलाम बनाकर उनका हरकदम शोषण कर 2-5 प्रतिशत धन सभी राजनीतिज्ञों को बांटकर भ्रष्टाचार करने में अपनी पूरी भूमिका निभा रही हैं। क्योंकि वो बहुराष्ट्रीय कं. ही अन्ना और केजरीवाल जैसों को अप्रत्यक्ष रूप से चंदा देकर स्वयं ही ऐसे सारे आंदोलनों को प्रायोजित करवाती है, ताकि अपनी लूट, वसूली पर जनता की ध्यान न जाये दूसरी तरफ जिन राजनीतिज्ञ नेताओं को धन देकर कठपुतली की तरह नचाते हैं। उन पर दबाव बनाकर अपने काम करवा सके। फिर भी न सुने तो आप पार्टी बनवाकर बड़े-बड़े राजनैतिक दलों पर झाड़ू चलवा देते है। सरकारी संपत्तियों,संसाधनों को मोटा कमीशन बांट कर हथिया लेते है। उनके विरूद्ध अन्ना, केजरीवाल ने अभी तक कोई आवाज क्यों नही उठाई। जिस केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के बीच लोग भाग रहे है। उसमें शामिल होकर भ्रष्टाचार के विरूद्ध लड़ाई लड़ने के लिये उन्हें स्वयं नहीं मालूम की भ्रष्टाचार की असली जड़ कहां और कैसी है। दूसरी और 700 लीटर पानी मुफ्त, आखिर 700 लीटर पानी का हर आदमी करेगा क्या, सारा दिन पानी में ही नहायेगा, लोट लगायेगा,या पेक करके बेंच कर अपनी रोजी-रोटी चलाने अर्तराष्ट्रीय स्तर पर अधिकतम 60 ली. पानी की जरूरत होती है। दूसरी और बिजली का बिल आधा 400 युनिट तक, एक आम आदमी के लिये 200 युनिट बिजली ही काफी है। 400 युनिट बिजली से न तो आम आदमी को एयर कंडीशनर चाहिये न दो कमरों के निवास पर ठंडी में हीटर चाहिये। गरीब आदमी और निम्न मध्यमवर्गीय को 200 युनिट बिजली टीवी, पंखे और रोशनी के लिये काफी है। आम आदमी को ज्यादा मुफ्त की सुविधायें देने पर वह खास हो जायेगा तो आम आदमी पार्टी चलेगी कैसे? कांग्रेस व उसके संपग्र गिरोह, भाजपा व अन्य दलों ने मिलकर जो लोकपाल कम जोकपाल बनाया। अन्ना ने आंदोलन समाप्त कर उसी कांग्रेस की उसे व्यर्थ के अधिनियम बनाने पर जो प्रशंसा की फिर राहुल ने भी अन्ना की प्रशंसा के जो कसीदे पढ़े उसने ही सिद्ध कर दिया कि अन्ना का आंदोलन कांग्रेस के कुकर्मों को बचाने का आवरण जिसे सेना की भाषा में स्मोक स्क्रीन कहते है था ताकि कांग्रेस अपनी लूट और कमीशन वसूली का खेल खेलती रहे, जनता का शोषण और खुलकर बर्बादी की जाती रहे, उसका ध्यान उस तरफ न जाने इसलिये उसे लोकपाल और भ्रष्टाचार के आंदोलन में उलझाकर रखा जाये।

जन स्वास्थ्य नहीं निरीक्षकोंसे नियंत्रक तक जेबों का स्वास्थ्य सुधार में व्यस्त

खाद्य व औषधी नियंत्रक से लेकर निरीक्षकों तक भ्रष्ट और जालसाज

सूचना के अधिकार की बिखेरते है धज्जियां-आकंठ भ्रष्ट कैसे दे जानकारी

मप्र में खाद्य और औषधी नियंत्रक विभाग में बैठे नियंत्रक डीडी अग्रवाल से लेकर नीचे तक बैठे 51 जिलों में बैठे सभी औषधि और खाद्य सुरक्षा अधिकारी या निरिक्षक तक सब ही जालसाजों और भ्रष्टों का अड्डा बन चुका है, सूचना के अधिकार में मुख्यालय से जानकारी मांगी गर्अ कि मुख्य विश्लेषक चतुर्भुज मीना का जाति प्रमाण पत्र, उ.मा. शिक्षा की अंकसूची प्रमाण पत्र और मूल निवासी प्रमाण पत्र के साथ ही उज्जैन देवास, और इंदौर के खाद्य व औषधि निरीक्षकों ने दी गई निश्चित अवधि में कितने नमूने लिये और कितनो के प्रकरण एसडीएम और न्यायालय में प्रस्तुत किये, 15 दिन बाद पत्र प्राप्त हुआ उज्जैन देवास,इंदौर को पत्र अंतरित कर दिया गया है, परन्तु जब तीनों जिलों के कार्यालयों में संपर्क किया तो, तीनों साफ बदल गए, कि कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ, जबकि तीनों के पास मु.चि. अधिकारी व उपसंचालक से पत्र पहुंचाया गया था, पर इंदौर में बैठे खा. सु.अ. स्वामी, देवास की खा. नि. श्रीमती पथरोल और उज्जैन के खा. नि. सचिन लोंगरिया तीनों हरामखोर, जालसाजों ने कोई जवाब नहीं भेजा, अंत में उसके विरूद्ध अपील की गई कि मुख्यालय से औश्र तीनों जिला कार्यालयों से कोई जवाब नहीं दिया गया है, धारा 7 (6) के अंतगर्त जानकारी उपलब्ध कराई जाये, बदले में मु.वि.च. मीना की एमएससी की माधव विद्यालय की अंकसूची और प्रति नियुक्ति पर उज्जैन से भोपाल की प्रतियां और एक-एक वर्ष के विस्तार की प्रतियां पकड़ा दी गई, आखिर मु.वि. च मीना जो कि पूरे प्रदेश के नमूनों को जांच कर सबकी जांच रिपोर्ट से प्रतिदिन की प्रति नमूना, रु. 25 से हजार वसूल रहा है, यदि 25 नमूने प्रतिदिन भी प्रतिदिन पास किये तो भी रु. 8-10 लाख प्रतिदिन की कमाई में से 10 प्रतिशत हिस्सा भी मु. नियंत्रक को मिल रहा है। अंदाज लगाया जा सकता है कि रु. 25 से 30 लाख प्रतिमाह की दुधारू गाय को कौन खूटे से छोड़कर भगायेगा फिर खाद्य सुरक्षा अधिकारियों, सह खाद्य निरीक्षक जो संस्था में पूरे प्रदेशभर में 150 से ज्यादा है। अधिकांश व्यापमं की परीक्षाओं में सन 2000 बाद भर्ती किये गये खाद्य सुरक्षा और मानक अधि. 06 में स्पष्ट प्रावधान है कि सभी तम्बाकू, गुटखा, पाउचों में नमूना लेकर सीधे ही न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया जाये, इसके विपरित पूरे प्रदेश के जिलो में उनकी तहसीलों और गांवों में बिकने वाले तंबाकू युक्त गुटखे पाउचों का ट्रकों से करोड़ों का माल पकड़ा जाने के बाद भी जो नमूने लिये गये वो सब ही पास कर दिये गये, बाद में पूरे प्रदेश में 51 जिलों में किसी भी खाद्य निरीक्षक सह खाद्य (कंपनियों के) सुरक्षा अधिकारी ने कं. के हितों कानून और सरकार को इच्छानुसार सारे गुटखा तंबाकूयुक्त पाउचों को जिनके लेन-देन की सेटिंग नहीं हो पाई, सबके प्रकरण एसडीएम के सामने प्रस्तुत कर सभी जिलों के एसडीएम और खाद्य निरीक्षकों ने लेन-देन कर निपटा दिये, जो कि पूर्णतः गैरकानूनी था, इसके विपरीत इस घोर अनियमितता और गैरकानूनी कार्य के विरूद्ध नियंत्रक ने भी कोई टिप्पणी नहीं की, जब इस संबंध में खा.सु.अ. मनीष स्वामी से पूछताछ की गई तो घूर्त उन्हें ही कहने लगा कि हमने सब कार्य कानूनी तरीके से ही किया है। सूचना के अधि. में जानकारी मांगी गई तो ये हरामखोर, जालसाज जानकारी न देने के लिये पंजीयो की फोटो की फोटो कॉपी की दरें बाजार दरों से कई गुना ज्यादा मांगी गई, जब अपील की गई, उपसंचालक स्वास्थ्य से गये सह. मु.चि.अ. डागरिया को, उसके स्पष्ट निर्देश देने के बाद भी वहां 4 से ज्यादा वर्षों से बैठा गिरोह जिसमें खा.सु.अ. मनीष स्वामी, सुभाष खेड़कर, अमित वर्मा आदि है। ने अपनी जालसाजियों वाह बचाने के लिये दो माह बाद भी जानकारी नहीं दी, दूसरी ओर ये गिरोह भी बाजार से वसूली में ही ज्यादा विश्वास रखता है। नमूने लेने की अपेक्षा वह इनके नमूने ले भी लिये तो भेजने से पहले ही अगर लेन-देन हो जाता है तो क्या जरूरत है, नमूने भेजने की, इसका दूसरा पहलू यह भी है कि अगर ये किसी शॉपिंग मॉल में घूसकर, नमूने लेने की कोशिश करते है तो खुले में उनके लठैत, अगर जान जाते है तो घूसने ही नहीं देते। फिर भी घूस गये और जान से मारने की खुली धमकी दी जाती है, दूसरी और ब्रांडेड कं. सीधे ही नियंत्रक, उपसंचालक, एसडीएम को सीधे ही उनके मुंह के आकार का टुकड़ा मासिक, त्रेमासिक जैसी भी दोनों पक्षों में सुविधा जम जाती है, इ मुखेरे श्वानों को डालती है तो कोई भी अधिकारी इन बहुर्राष्ट्रीय कं. के नमूने लेने की तो दूर उन्हें ही नमूने ले लेने पर फोन पर ही धमका कर कार्यवाही स्थगित करवा दी जाती है। इससे ये खाद्य निरीक्षक काफी हतोत्साहीत हो जाता है। इनके साथ यह एक बड़ी विडम्बना है, इन्हें छापे डालने, नमूने लेने के लिये एसडीएम और मुख्य चि.अ. जो इनका उप संचालक भी होता है, उससे आज्ञा लेने या निर्देश के अनुसार ही कार्य करना पड़ता है, ये दोनों ही हरामखोर अधि. एक तरफ महीना खाने और दूसरी तरफ अपने संबंध निभाने के लिये इन्हें जानबूझकर न तो कार्यक्रम देते है न ही निर्देशित करने के लिये छोटे खाद्य विक्रेताओं, फैक्ट्रियों पर कार्यवाही करने तक सीमित हो जाते है। इसी स्वास्थ्य विभाग के अंतगर्त कार्यरत इसी विभाग में औषधि विभाग की जो अलग शाखा है, वहां भी एक तो पूरे प्रदेश के 51 जिलों में मात्र 35-40 निरीक्षक है। ये पूरा गिरोह भारी जालसाजों, डकैतों का वसूलीबाज गिरोह के बल येन-केन प्रकरेण चमका-धमका कर रु. 50 हजार से लाखों रु. तक प्रतिदिन की वसूली करने में ही व्यस्त रहता है, यही कारण है कि प्रदेश के 51 जिलों में कम से कम प्रति जिले के 5 के हिसाब से 255 और इंदौर-भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और मुख्यालय के लिये जो उत्पाद में उद्योग नियमित जांच आदि के लिये 50 औषधि निरीक्षक अर्थात कम से कम 300 औषधि निरीक्षक होने चाहिये जो नियमित रूप से न केवल औषधि विक्रेताओं वरन अस्पतालों, रक्त कोषों, नर्सिंग होम्स उनमें उपयोग की जाने वाली औषधियां मशीन प्रदान की जा रही सुविधाओं आदि की कीमतों, सौंदर्य प्रसाधनों आदि पर नियंत्रित रूप से कड़ी निगरानी कर सके इसके विपरीत 51 जिलों में मात्र 35-40 औषधि निरीक्षकों इनका गैंग लीडर शोभित कोष्टा, उप संचालक एवं वरिष्ठ निरीक्षक शोभित कोष्टा जिसका जाति प्रमाण पत्र ही संदेहपस्थ है, जिसे अनेको बार मुख्यालय से मांगने पर भी वर्षों बाद नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि कोष्टा जाति अनुसूचित जाति में पूरे प्रदेश में मान्य है,जबकि बंदा अनुसूचित जनजाति का प्रमाणपत्र पर न केवल नौकरी कर रहा है वरन अनु. जनजाति का लाभ लेकर अपने सभी वरिष्ठ अनु. जाति वालो को पीछे छोड़कर उप संचालक बनकर संयुक्त संचालक का पद संभाल रहा है, जिससे पूरे मप्र की 500 से ज्यादा दवा उत्पादक कंपनी से जिसमें अकेले इंदौर, देवास, पीथमुर की 50 से ज्यादा जिसमें रेनबेक्सी, प्लेथिको, इप्का जैसी कं. से 50 लाख से ज्यादा, जबकि अकेले इंदौर के दवा बाजार से ही रु. 21 लाख प्रति माह, इसके अंतगर्त 700 दुकानों से रु. 3000/- प्रति माह के हिसाब से वर्तमान में औषधि निरीक्षक भिगोनिया ही वसूली कर रहा है, जिसका 50 प्रतिशत हिस्सा भोपाल जा रहा है, जबकि यहां पर बैठा ओ.नि. वृन्दानी रु. 50 लाख प्रतिमाह की कमाई इंदौर संभाग के आठ जिलों से कर रहा है, बिना मु.चि.अ. और एसडीएम की स्वीकृति के बिना वृंदानी और औ.नि. भिगोनिया यात्रा कार्यक्रम संपन्न आठों जिलों के औषधि विक्रेताओं, नर्सिंग होम्स और अस्पतालों में घुसकर हर दिन रु. 2 से 5 लाख की वसूली कर रही हैं। सूचना के अधिकार में सीधे और प्रधान कार्यालय से आये पत्रों का इसी प्रकार जवाब नहीं दिया जा रहा है, दूसरी और महीना वसूली के चलते न तो कहीं से किसी भी दवा विक्रेता का निरीक्षण किया जा रहा है कि वे कैसे और कौन सी दवायें किस बैच नं. की चालू अवधि की या समय बाधित दवायें बेच रहा है। यह हाल पूरे मप्र का ही है, व्यापमं द्वारा सन 2000 के बाद भर्ती किये गये सभी औषधि और खाद्य निरीक्षक सभी संदेहास्पद ही हैं। स्पष्टतः अधिकांशतः पैसा खर्च करके ही भर्ती हुये है। स्वाभाविक है कि, सब का उद्देश्य वसूली करना ही है, न कि जनता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना, वर्तमान में कार्यरत अधिकांश औषधि निरीक्षकों ने न तो किसी औषधि उत्पादक से, न ही किसी थोक और फुटकर औषधि विक्रेता से महीनो से औषधियों के न तो नमूने लिये है न ही किसी की जांच की है, हां यह अवश्य है कि जांच के नाम पर कुछ वर्षो पूर्व औ.नि. अजय ठाकुर, अशोक गोयल भर्ती हुए जैसे औषधि निरीक्षक भी रु. 1 लाख प्रतिदिन तक की वसूली अवश्य जांच के नाम पर, नारकोटिक्स के नाम पर वसूल रहे हैं। जिससे यहां भी जांच के नाम पर जाते हैं, रु. 25000/- से कम में सौदा नहीं करते। ये सूचनाएं दुकानदारों में अवश्य मिली है। अन्यथा क्षेत्र प्रभारी हर दवा दुकन से रु. 5000/- वर्ष में दो बार वसूल करता है, इंदौर में लगभग 2000 से ज्यादा फूटकर दुकानदार हैं। बैशक औषधि निरीक्षकों को भी इस वसूली में उपसंचालक सह मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. डागरिया, एसडीएम से लेकर अपने नियंत्रक को भी महीना पहुंचाने के साथ स्थानांतरण पदस्थापना में भी रु. 5 से 10 लाख तक खर्चने होते हैं। इसलिए स्वाभाविक है, सूचना के अधिकार में दिये सारे पत्रों को पद, धन और बल के दम पर हजम कर जाते हैं। लोकायुक्त चाहे तो इंदौर में पदस्थ मात्र एक औषधि निरीक्षक वृंदानी की कॉल डिटेल्स निकलवाकर उसकी वसूलीयों और संपत्तियों का पता लगा सकती है, जो रु. 25 करोड़ से ज्यादा ही निकलेगी।

करोड़ों को बेरोजगार बनाकर जीने योग्य बांटी जायेगी भीख

पेज 1 का शेष

इस कानून के अंतर्गत पूरे देश के 50 लाख से ज्यादा अधिक फुटपाथ और ठेले पर सब्जी बैचने वालों से लेकर 50 लाख से ज्यादा एकल चाय, पान, किराना बेचने वाले खाद्य वस्तुओं में उत्पादन पेकिंग तक करने वाले, परिवहन व आपूर्ति करने वाले लगभग 6 करोड़ और किसानों और कृषि कार्य से जुड़े 5 करोड़ लोग इनका व्यवसाय करने वाले 1 करोड़ व्यवसायी आढ़तियों को बेरोजगार कर दिया जायेगा।

खाद्य सुरक्षा और मानक अधि.06 वास्तविकता में इन धूर्त बहुराट्रीय कं. के बड़े लाभ की सुरक्षा और इन राजनीतिज्ञों जिसमें भाजपा, सपा, बसपा, लोकदल, जदयू , बीजेडीख व अन्य सभी दलों के मासिक वार्षिक मोटे कमीशन की व्यवस्था की गई है, यह ईस्ट इंडिया कं. के गुलामी के कानून से ज्यादा घातक सिद्ध होगा,देश की धरती पर देश के संसाधनों से पैदा की गई खाद्यान्नों पर इस कानून के पूर्ण रूप से 5 फरवरी 2014 से लागू होने के बाद किसान अपनी मेहनत और कर्ज से पैदा की गई खाद्यान्नों, दलहन, साग, सब्जी, फल-फ्रूट आदि को बाजार या मंडी में ले जाकर नहीं जा सकता यदि जायेगा तो रु. 50000 से लेकर 5 लाख तक अर्थदंड और 6 माह के कारावास की इस कानून में व्यवस्था कर दी गई हैं, ताकि किसान के माल को गिद्ध बहुराष्ट्रीय कं. अपने मनमाने भावों में, खेतों से ही खरीदकर अच्छे माल को दोगुनी से 100 गुनी कीमतों में अतर्राष्ट्रीय बाजारों में घटिया माल को भारत की गरीब जनता को दोगुनी से 10 गुनी कीमतों में बैचकर मनमाना लाभ कमा सकें। जैसा की रु. 2 किलो के आलू की कीमत को रु. 15 के पेकिंग में 20 ग्राम बेचा जा रहा है, जिसमें आईटीसी, रिलायंस, केडबेरिज, हिन्दुस्तान लीवर तक सब शामिल है, अर्थात रु. 2 प्रतिकिलो की कीमत 300 गुना ज्यादा में हमें ही बेंच रही है। अभी आलू प्याज है, कल दाले सभी सब्जियां एकाधिकार होने पर बेचेगी अर्थात सरकारी रु. 1 प्रति किलो के गेहूं-चावल का कमीशन इन भुखेरे राजनैतिक पार्टीयों के नेताओं को टुकड़ों के रूप में डाल दिया जायेगा, ये सारे भाजपाई, कांग्रेसी, आप, सपा, बसपा, सब टुकड़ा चबा कर चुप रहेंगे। जब किसानों को उनकी फसल का पूरा मूल्य नहीं मिलेगा तो स्वाभाविक रूप से आत्महत्या कर लेगा अन्यथा अपनी जमीनें इन धूर्त बहुराष्ट्रीय कं. को बैच देगा। इस प्रकार देश के 5 करोड़ किसान और कृषि कार्यों से जुड़े लोगों को बेरोजगार बना दिया जायेगा। बदले में जो मनरेगा लागू की गई है, उस का उद्देश्य ही था कि ग्रामीण मजदूरों को कृषि कार्यों से अलग कर छोटे किसानों को कृषि घाटे का सौदा बनाकर जमीने हथियाना और अकेले 31 मार्च 2013 तक आईटीसी ने पूरे देश में 20 लाख हेक्ट. जमीने हथया ली थी। पूरे देश में ये पूंजीपति 2015 तक 2 करोड़ हैक्टेयर जमीन हथिया लेंगे।

समय माया ने इन तथ्यों को सन 2006 से इस कानून के बारे में लगातार प्रकाशित किये, देश के सबसे बड़े व्यापारिक संगठन फेडरेशन ऑफ चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने माना कि इससे 5 करोड़ लोग बेरोजगार कर दिये जायेंगे। कांग्रेस इसे लागू नहीं करवा पाई, उसने अन्ना से गुपचुप तरीके से हाथ मिलाकर लोकपाल के लिये आंदोलन करना शुरू कर भीड़ इकट्ठी करना शुरू कर दी, 23 जुलाई 2011 में जब भीड़ का उत्कर्ष आया तो उसे बूढ़े कांग्रेसी एजेन्ट अन्ना ने घोषणा कि अब आंदोलन 16 अग 11 से करेंगे। कांग्रेस ने 5 अग 11 से मौका पाकर इसे सारे देश में लागू कर दिया, जब इस सत्यता को जन 12 में प्रकाशित किया तो पूरे मप्र के व्यापारियों ने 9, 10 व 11 अप्रेल 12 को मप्र बंद का आव्हान कर दिया और इन तीन दिनों में प्रदेश की 7 करोड़ जनता को इस अधिनियम की सत्यता का यथार्थ समझ आया, तब शिवराज ने चुनाव के मद्देनजर 1 वर्ष तक के लिये अधि. को लागू करना टाल दिया, पर चुनाव में जीत मिलते ही उसने इस अधिनियम को ध्यान में रखकर जिससे पूरे प्रदेश में 1 करोड़ खाद्य वस्तुये बिक्री, उत्पादन, पेकिंग, परिवहन करने वालों से लेकर, जिसमें 50 लाख कृषि कार्य और उनसे जुड़े लोग व रोजगार होंगे तो चिलायेंगे इसलिये आते ही रु. 1 किलो में चावल और गेहूं जिसकी पिसाई शहरों रु. 3 से 5 प्रति किलो और गांवों में रु. 5 से 7 प्रति किलो की जाती है देने की घोषणा कर दी, परन्तु दाल दो साल में रु. 100 से 200 प्रतिकिलो हो जाएगी। प्याज रु. 100 बिक चुकी है। आलू की शीघ्र ही रु. 25 से 50 प्रतिकिलो बिकने लगेगा तो गरीब रोटी चावल बनाकर नमक के साथ खायेगा। दाल-सब्जी सपना बन जाएगी। इसी कारण केन्द्र के कांग्रेसी गिद्ध पूरे देश को जो 10-15 करोड़ बेरोजगार उनसे जुड़े लगभग 70 करोड़ लोगों को खाद्य सुरक्षा देने की बात कर रु. 1 प्रति किलो गेहूं देने की बात करती है।

केजरीवाल की आप जिसकी लहर में पूरा देश बह रहा है और मीडिया भी कांग्रेस की शह पर इसलिये उछाल रहा है कि किसी प्रकार भाजपा को सत्ता से दूर रखा जाये, जबकि अरविन्द केजरीवाल ने टाटा, बिरला, अंबानी, सुनील भारती, आईटीसी से मोटा चंदा डकार कर चुनाव तो लड़ा ही परन्तु उनके भ्रष्टाचार, उनकी लूट डकैती के बारे में किसी ने भी उंगुली नहीं उठाई, जबकि उच्च स्तर पर भ्रष्टाचार के लिये सभी पूंजीपति, उद्योगपति, बहुराष्ट्रीय देशी विदेशी कं. इन्हें मोटा धन बांट कर पूरा देश खाद्य वस्तुओं के व्यापार हथिया कर बेरोजगारी और गुलामी लाना चाहती है। पर इस देश की भेड़ चाल चलने वाली जनता को सच कब समझ आयेगा, आवश्यकता इस बात की है कि खाद्य व्यापारी जो चाय दुकान, सब्जी भाजी ठेले लगाने से लेकर रु. 6 लाख से 30 लाख तक का व्यापार करता है, पिछले वर्ष की तरह पूरे देश में एकत्रित होकर राष्ट्र व्यापी आंदोलन कर इस अधिनियम को रद्द करवाकर पुनः खाद्य अपमिश्रण निवारण अधि. 1954 लागू करवाये जो वास्तविकता में खाद्य में मिलावट और स्तरहीनता को रोकने के साथ कीमतों पर नियंत्रण रखने में भी प्रभावी है। जब कांग्रेस ने इस अधिनियम को पूरे देश में लागू किया तब उस संयुक्त संसदीय समिति का शिवराज भी सदस्य था। देशी-विदेशी कं. द्वारा इस अधि. को बनाने और लागू करने में बंटे हजारों करोड़ रु. में शिवराज भी हिस्सेदार था, इसलिये जानबूझकर किसी भी राजनैतिक पार्टी ने न केवल इस अधि.का विरोध लोकसभा और राज्यसभा में भी न करने के साथ, चुपचाप देश में लागू करने में मुखेरे कमीशनखोर मुख्यमंत्रियों या राज्यों की विपक्षी पार्टियों ने भी हिचकी तक नहीं ली, जबकि बनाते समय ही स्पष्ट हो चुका था कि 10 करोड़ बेरोजगार होने से 60 करोड़ गरीबी रेखा के नीचे आ जायेंगे।

साप्ताहिक समय माया

कैसे जीते सरकारी अधिकारी-कर्मचारी का अंधा स

वाह शिवराज सरकार-

बकवास है,पारदर्शिता और भ्रष्टाचार दूर करने का वादा, भूमाफिया आदि बैचारे शिव कैसे करें गणों से युद्ध।1 मंत्री हारे हैं,बाक

मप्र में शिव ने तीसरी बार भी सरकार बना ही ली इसलिये नहीं कि शिव या उनके गणों ने बहुत ईमानदारी से जनता के हितों से काम किये वरन जनता के पास मात्र दो ही विकल्प थे, कांग्रेस या भाजपा, नेता - भ्रष्टाचार लूट, जालसाजियों के पर्याय बन चुके हैं चाहे मप्र के या पूरे देश के या पूरी दुनिया के, यहां ईमानदार वह है, जिसे बेईमानी का मौका नहीं मिला? फिर नेतागिरी का धंधा कभी नहीं हुआ मंदा मौका मिलते ही भीड़ की अगुवाई करते ही, नेता का काम ही है, जो पीछे खड़े है, उनको भी लूटो और जो आगे खड़े है उनको धमका-चमका कर अपनी कमाई का रास्ता बनाकर आगे निकलो, यह हर नेता का परम ध्येय है, बस सवाल है कि कौन कितना बड़ा बेशर्म, चालाक, घूर्त इंसान है और कैसे किस तरह अपनी गोटिया जमाकर लूटमार वसूली करता है। भाजपाई अब समय के साथ न केवल भ्रष्टाचार करने में वरन धन, बल व छल के साथ ही शासकीय मशीनरी से लेकर ईवीएम तक पर सेटिंग में पारंगत हो चुके है, इसी का परिणाम था। 2013 के विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत पर बहुमत का मूल कारण यह भी था कि, जनता को कांग्रेस की वर्तमान केन्द्र सरकार ने महंगाई का और पूर्व की मप्र की दिग्गी दानव की अंधेरे,महंगाई, गड्ढे वाली सड़कों के दिये घाव भरे नहीं, उस पर प्र.म.म.मो. सिंग, नमक छिड़क कर घाव हरे करते रहे है। अब बेचारी जनता को एक तरफ खाई, दूसरी तरफ कुआं में से खाई में गिरने का विकल्प चुना क्योंकि खाई में गिरने के बाद कम से कम जान सलामत रह सकती है, तीसरा महत्वपूर्ण कारण था कि न केवल भाजपा की सरकार ने पिछले 5 वर्षों में वेतन,भत्तों में न केवल कई गुना बढ़ोत्तरी की वरन यथा संभव कर्मचारी अधिकारियों को खुश रखने का प्रयास भी किया। दूसरी तरफ भाजपाई मंत्रियों का ढीला प्रशासन और वसूली की प्रक्रिया भी भेड़ियों की तरह मिला तो भी खुश न मिला तो भी ज्यादा मलाल नहीं। जबकि दिग्गी दानव और उसके मंत्री तो अधिकारियों से स्थानांतरण, बचाने नियुक्ति पर स्थापना में वसूली से लेकर महीना भारी वसूली करते थे। न मिलने पर तेंदुओं की भांति झपट कर नोंचने लहूलूहान भी कर देते थे, इसलिये सरकारी मशीनरी में चुनाव व आयुक्त से अदने बाबू चपरासी ने एकमत हो अंध सहयोग कर भाजपा को जिताया।

इस राष्ट्र की केन्द्रीय सत्ता, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रियों, राज्यों को मुख्य मंत्रियों से लेकर राज्यों के मंत्रियों, जिलाधीशों और अंतिम मप्र प्रशासनिक छोर पर बैठे जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों के रूप में बैठे इंडियन एव्यूसिंग सर्विस अधिकारियों द्वारा राष्ट्र की शीर्ष सत्ता से लेकर अंतिम छोर तक प्रशासनिक व्यवस्थाएं संभाली जाती है। भाजपा और उसके मुख्यमंत्री शिवराज ने इसलिये किसी भी आईएएस को न केवल नराज नहीं किया वरन आर. परशुराम जैसे भ्रष्ट, निकम्मे, जालसाज को न केवल मुख्य सचिव बनाया वरन सेवा विस्तार किया। सेवानिवृत्ति 30.09.13 के पूर्व ही पत्र क्रं. एफ19-31/2006/1/4 दिनांक 17.09.2013 से भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के खंड एच का हवाला देकर 6 वर्ष या 66 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक राज्य निर्वाचन आयोग का आयुक्त नियुक्त करवाने के लिये पत्र जारी करवा लिया।

मु.म. शिव की उदारता से कार्यरत भा.प्र. से. का गिरोह नाराज तो हुआ परन्तु इस तथ्य को लेकर खुश था कि ऐसा ही अवसर उनको भी भविष्य में मिलेगा, इसलिये भारतीय प्रशासनिक सेवा के इन धूर्तों का भी मुक्त हृदय से आर्शीवार्द मिला जो ईवीएम मशीन में सेटिंग करने का जालसाजी पूर्ण मतदान करवाने में सिद्ध हस्त है, जिसने चुनाव में भारी बहुमत दिलवाया और इससे न केवल प्रदेश कांग्रेस चारों खाने चित्त हो गई वरन केन्द्रीय सत्ताधीश कांग्रेसी राक्षसी गिरोह को दिन में तारे नजर आने लगे, इस जीत पर न केवल प्रदेश की जनता वरन पूरे राष्ट्र की जनता इसलिये खुश नजर आई कि डकैतों के चंगुल में फंसने से बचे। चोरों का चंगुल ज्यादा घातक नहीं, फिर भाजपाई मु.मं. शिवराज की विनम्र शैली, गल्तियों की क्षमा मांगने और भविष्य में बेहतर करने का इरादा और वादा, जीत का आधार भी रहा।

शपथ ग्रहण करने के पूर्व और पश्चात जनता से भ्रष्टाचार दूर करने, पारदर्शिता लाने प्रशासनिक कसावट के वादों में इच्छा शक्ति अवश्य झलकी परन्तु केवल नौटंकी ही थी, जिसमें उच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद भी मुख्य सूचना आयुक्त, 4 आयुक्त और 9संभागों में सूचना आयुक्तों के संबंध में, 12 दिन तक नियुक्ति का वादा, हवा हवाई होना, सूचना आयोग में चयन प्रक्रिया में वर्तमान और सेवानिवृत्त घूर्तों का गिरोह इंडियन एव्यूसिंग सर्विस ही महज उन्हीं के आवेदन स्वीकारना स्पष्टतः खोटी नियत और जालसाजी का परिचायक है। दूसरी और ई-गर्वनेंस जालसाजी पूर्ण तरीके से राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार अवश्य प्राप्त कर लिया, जबकि इन हमरामखोरों ने सूचना अधिकार में आवंटित मप्र का बजट केन्द्र सरकार से लेकर हजम कर गये और हर वर्ष मिलने वाला हर विभाग, हर जिले में आवंटित बजट भी हजम कर जाते हैं। पर 8 वर्ष गुजर जाने के बाद कई विभागों की ग्रामीण शाखाओं में या कम्प्यूटर ही नहीं है, अगर हैं तो या उन्हें जानबूझकर खराब कर दिया गया है। इस केन्द्र सरकार के बजट इस सूचना अधि. 2005 की धारा 4 (1) के 17 बिंदूओं की जानकारी संबंधित विभाग के हर कार्यालय क़ा इंटरनेट साइट पर होनी चाहिए जो अभी तक नहीं किया गया, जो 10 वर्ष की सरकार के इतिहास और अगले 5 वर्ष के भविष्य की स्पष्ट व्याख्या है।

उपरोक्त सब तथ्यों को यदि नजरअंदाज भी कर दिया जाये तो मु.म. शिवराज की पारदर्शिता और भ्रष्टाचार की नौटंकी का पर्दाफाश नवगठित मंत्रिमंडल से पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है।

मु.म. शिवराज ने पांच विभाग जिसमें सामान्य प्रशासन अर्थात पूरे प्रदेश के सभी जिलों, संभागों के जिलाधीशों, आयुक्तों से लेकर हर विभाग के प्रधान सचिव, आयुक्तों, संचालकों प्रमुख अभियंताओं, डॉक्टरों आदि की नियुक्ति, पदोन्नतियां, पदस्थापनाओं से लेकर जालसाजी पूर्ण गजट नोटिफिकेशन, राजस्व से सीधी वसूली पाइप लाइन की, सीधा संपर्क लोकसभा चुनाव की तैयारी में वही सब दोहराया जा सके जो विधानसभा में दोहराया गया।

नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण में पुराने अधूरे कार्यों, गुणवत्ताहीन, नहर निर्माण करने वाले ठेकेदारों को जिन्हें हजारों करोड़ रु. के ठेके जो दो-ढाई वर्ष के लिये दिये गये थे, चूंकि सीधी वसूली की गई 5 से 8 वर्ष बाद भी पूरे नहीं हुये। एक तरफ वीसी विहानी, करणसिंह जैसे वह शूकरीय, जालसाज, निकम्मे ठेकेदार जिनके पास सैकड़ों करोड़ के वर्षों से ठेके है तो दूसरी तरफ महानिकम्मे, भ्रष्ट, ढीला उपाध्यक्ष रजनीश वैश्य तो सदस्य अभियांत्रिकीय इंगले जो महाकुकर्मी, ब्योडा, डकैत जिसे सेवानिवृत्ति के दो वर्ष लूटने और लुटाने के लिये सदस्य अभि. बनाया गया, पिछले 10 वर्षों का इतिहास ही अगले 5 वर्ष दोहराया जा सकेगा, बाकी विमानन, संस्कृति और पर्यटन भी इन्हीं के पास है। शिव ने अपने गणों में अपने अधिकांश पुराने भ्रष्ट, जालसाज, भूमाफिया, खदान माफिया, शिक्षा माफिया, दलालों आदि को उनकी क्षमताओं, वसूली आदि के अनुसार जगह दी है, पूरे 23 में कोई भी अच्छा प्रशासक, ज्ञानी और विशेषज्ञ नहीं है, कइयों पर पूर्व से ही लोकायुक्त में जांचे, प्रकरण आदि लंबित है। अर्थात वाह रे शिव तेरी सरकार हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमार

मंत्री बाबुलाल गौर- गृह एवं जेल

परिणाम अपराध बढ़ेंगे, गुंडों, माफियाओं, ड्रग तस्करों, अवैध कारोबारियों, वसूलीबाजों, नेताओं, भूमाफियाओं, खनन माफियाओं, सटोरियों, जुआरियों, अवैध कब्जे करने वालों पर पुलिस मेहरबान रहेगी, यदि जनता और प्रशासनिक दबाव के चलते जेल में पहुंचा भी दि गये तो अपराधियों को धन खर्च कर जेल से अवैध करोबार चलाने में जेल अधिकारियों का ही सहयोग मिलेगा। प्रशासनिक स्तर पर गिनती के बाद परिणाम आने पर ही अधिकारियों के बीच ये गुटर-गू चल रही थी, पुलिस और जेल प्रशासन नेतागिरी से त्रस्त-त्रस्त रहेगा। अपराध कम दर्ज हो इसलिये 100 नं. पुलिस का 90 प्रतिशत प्रदेश के 51 जिलों में सेवा में नहीं है। सीमा से बाहर है, थोड़ी देर बाद डायल करें। सभी लाइने व्यस्त हैं, सुनाता आया है। अगले 5 वर्ष भी सुनायेगा। थानों में वैसे भी मात्र 5 प्रतिशत मामलों की ही शिकायतें एफआईआर में बदलती है। 95 प्रतिशत अपराध पुलिस वाले दर्ज ही नहीं करते है। आतंकीयों, तस्करों, भूमाफियाओं वन माफियाओं, खदान माफिया, नशे के कारोबारियों का मप्र शरणगाह है। हर माह रु. 1500 से 2000 करोड़ की वसूली की जाती है। गौर का अपना हिस्सा रहेगा।

मंत्री सरताज सिंह- लोक निर्माण विभाग

होशंगाबाद, भोपाल, इंदौर संभाग के सभी जिलों के वनों की अवैध कटाई, वन प्राणीयों और उनके अंगों की तस्करी के पुराने माफिया पूर्व में वन विभाग ही था, अब मप्र लोक निर्माण विभाग मंत्रालय संभालेंगे। 5000 किमी से ज्यादा की सड़के बीओटी ठेकेदारों के चंगुल में जो महीना मिलेगा फिर भ्रष्ट मानसिकता के है। तो क्या-क्या एक तरफ विभागीय भवन निर्माण माफिया, सड़क निर्माण माफिया ठेकेदारों और उनके अधिकारियों इंजिनियरों पर मजबूत पकड़ बना पायेंगे। वर्षों से अटक रहे पुलों जो महाभ्रष्ट और निक्कमें इंजिनियरों के कारण अधूरे है। मप्र सड़क विकास निगम जहां चुन-चुन कर लो.नि.वि के इंजिनियर बैठाये गये हैं, जिन्हें बीओटी के ठेकेदारों की जी हुजूरी करना है, सड़के कैसी भी हो ठेकेदारों को टोल वसूली करना है। स.वि.नि. के इंजिनियरों को सरकार के बराबर महीने का वेतन देकर मुहं चुप रखना है। वही हिस्सा कुछ मंत्री लगभग रु. 10000 करोड़ जिसमें सीआरएफ, शिक्षा, चिकित्सालयों के निर्माण की राशि भी है में ही मंत्रीजी को हिस्सा मिलेगा, पर उनकी क्षमतायें लोकसभा चुनाव परिणाम निश्चित करेगी।

मंत्री पारस जैन-स्कूली शिक्षा

उज्जैन का ये भूमाफिया, मंत्री अब शिक्षा माफिया का सरदार बन प्रदेश के लगभग 50000 से ज्यादा स्कूलों जो निजी क्षेत्र में चल रहे है। वसूली का सरगना बनेगा स्वाभाविक है, वे निजी स्कूल विद्यार्थियों के माता-पिता और पालकों को लूटेगा, फिर स्कूली शिक्षा में केन्द्र और राज्य से मिलने वाले रु. 5000 करोड़ जो सर्व शिक्षा अभियान, स्कूल उन्नयन, निर्धन छात्रों के गणवेश, पुस्तकें, सायकलें, छात्रवृत्ति, मध्यान्ह भोजन, स्कूल की खरीदी के लिये आवंटन करता है, उसके 10 से 20 प्रतिशत का हिस्सेदार भी बनेगा, निजी क्षेत्र में शिक्षा का व्यापार भारत की और प्रदेश की युवा पीढ़ी का बहुत ज्यादा भला भले ही नहीं कर पा रहा हो, परन्तु शिक्षा के निजीकरण और व्यावसायिकता ने एक तरफ न केवल शिक्षा का स्तर और विश्वसनीयता समाप्त की है, तो दूसरी तरफ आम गृहस्थ नागरिकों की युवा होती पीढ़ी को शिक्षित करना भारी महंगा और दूभर कर दिया है। गरीबी रेखा से ऊपर, निम्न मध्यमा वर्गीय परिवारों में दो बच्चों की फीस में ही जो प्राथमिक माध्यमिक में 25 से 50 प्रतिशत कुल आय खर्च हो रही है, फिर इनका ये 5 वर्ष अंतिम ही होगा जहां ये खुलकर लूट, वसूली और मौज मनायेंगे। जबकि शिक्षा को सर्वसुलभ, सस्ती और गुणवत्ता पूर्ण बनाकर ये ठस वसूलीबाज न केवल अपना,पार्टी प्रदेश और देश का भविष्य संवार सकता है।

मंत्री जयंत मलैयाः वित्त, जलसंसाधन, आबकारी, वाणिज्य कर

प्रदेश के वित्त मंत्री स्वयं पूर्व से ही व्यापारी रहे है। टैक्स चोरी विशेषज्ञ, महाभ्रष्ट वसूली बाज केन्द्र और राज्य के वित्त आवंटन में पहले मंत्री जी और उनके गिरोह का हिस्सा निकाल और ले, वाणिज्यकर आबकारी से लगभग पूरे प्रदेश से ही रु. 10 अरब की न्यूनतम कमाई, कर चोरों और शराब माफिया के हौंसले बुलंद, जल संसाधन केन्द्र और राज्य की सिंचाई परियोजनाओं में रु. 10 हजार करोड़ से ज्यादा का बजट, प्र.स.रा. श्याम जुलानिया ने न केवल विभाग की छवि सुधारी वरन सिंचाई का रकवा बढ़ाने के लिये मैदानी इंजिनियरों और कर्मचारियों की खुलकर खिंचाई की, परन्तु अधिकांश योजनायें कछुआ चाल से ही चल रही है। मंत्री वाणिया लक्ष्मी प्रेमी, प्र.स. कार्य प्रेमी से भी दोनों की पटरी नहीं बैठ पा रही है। स्वाभाविक मलैया, प्र.स. की हटाने के फेर में लग रहे, केवल आबकारी की 10 प्रश आय को 50 प्रश और वाणिज्यकर की आय जो 30-35 प्रतिशत जो व्यापारियों की निजी फर्मों व कंपनियों से मिल रही हैं। 60-70 प्रश पर लाकर प्रदेश की वित्तीय स्थिति को मजबूत कर सकते हैं।

मंत्री गोपाल भार्गव- पंचायत एवं ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय एवं सहकारिता

मंत्री का भ्रष्टाचार और वसूली का इतिहास है, फिर तीनों ही विभाग अपने भ्रष्टाचार के लिये हर दिन समाचार पत्रों की सुर्खियों में रहें। पंचायत एवं ग्रामीण विकास में 50 से ज्यादा योजनाओं जिसमें मनरेगा, मध्यान्ह भोजन आदि की महत्वपूर्ण योजनायें है। जिला, जनपद और ग्राम पंचायतों के अरबों रु. प्रतिवर्ष का हेर-फेर करते हैं। मंत्री को भी हिस्सा पहुंचता है, इसलिये किसी भी भ्रष्ट का कभी कुछ नहीं बिगड़ता, सामाजिक न्याय का अधिकांश पैसा कागजों पर ही खर्च हो जाता है, सहकारिता का तो अर्थ ही है, सहकार मिल कर करो बंटाधार। फिर उसमें ग्वालियर के डकैत का संरक्षण। अपैक्स बैंक के मुख्यालय से लेकर ग्राम समितियों तक, सहकारी साख संस्थाओं, गृह निर्माण उचित मूल्य की सहाकारी संस्थाओं में लूट-खसोट का तांडव मचा रहता है। वर्षों ऑडिट नहीं होते, उचित मूल्य की राशन की सहकारी साख संस्थायें तो यथार्थ में एकल व्यावसायिक संस्थाये है, जहां 30-40 वर्षों से चुनाव तो दूर ऑडिट भी नहीं हुए है। खुले में सरकारी अनाज गेहूं, चावल आदि शक्कर, मिट्टी का तेल आदि 25 प्रश ही गरीबों को मिलता है। 75 प्रतिशत कोटे की ब्लेक मार्केटिंग से हजम कर लिया जाता है। हर लूट में मंत्री जी का हिस्सा।

मंत्री डॉ. गौरीशंकर शैजवारः वन, जैव विविधता एवं जैव प्राद्योगिकी

वन विभाग को न केवल राज्य और राष्ट्रीय बजट मिलता है, वरन अंतर्राष्ट्रीय संस्था विश्व वन्य प्राणी निधि से भी अ. डा. 2000 करोड़ जिसकी वर्तमान में भारतीय रुपए एक लाख 30 हजार करोड़ मिलते है, केवल कागजों में वन प्राणियों की संख्या दिखाने और कागजों पर ही उनकी जनसंख्या बढ़ाने खाने पीने और रहने की मौलिक परिस्थितियां देने के लिये जिसका एक पैसा न केवल नीचे खर्च नहीं होता, सब हजम कर लिया जाता है, फिर वन विभाग के वन्य प्राणियों में सबसे घातक भ्रष्ट और जालसाज इंडियन फारेस्ट ईटिंग सर्विस के अधिकारियों की संख्या हर वर्ष गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ जाती है। वहीं प्राकृतिक वन्य प्राणी हरात्मक श्रेणी में घटते जा रहे है। वहीं हाल वन भूमि वनों का भी है। मैदानी क्षेत्रों में काम करने वालों में रेंजरों से लेकर वीट गार्डों, कार्यालयों में जन्तुओं की संख्या लगातार वर्षों से भर्तीया न होने से घटती जा रही है। पूरे प्रदेश में इससे अवैध वन कटाई, वन भूमि पर कब्जे जिसमें अधिकारी भी शामिल होते है। वनोपज की अवैध बिक्री, खनन माफिया आदि इन सबका रु. 1 लाख करोड़ से ज्यादा की अवैध करोबार जिसमें दुर्लभ प्राणियों, जड़ी बूटियों की तस्करी भी है। दूसरी और वनों के विकास, वन ग्रामों के विकास में खर्च किये जाना वाला धन भी रेंजरों से लेकर मंत्री तक हजम कर लिया जाता है। शैजवार को इन सब पर रोक लगाकर वनों को प्राकृतिक विकास करना चाहिये।

हयोग, ईवीएम जालसाजी, कांग्रेस के दिये घाव हरे

हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमार

को नगरीय प्रशासन, सूदखोर को वित्त, खदान माफिया को खनिज
की धन, छल से जीते,भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी,अपराध बढ़ेंगे

मंत्री कैलाश विजयवर्गीयः नगरीय प्रशासन एवं विकास आवास एवं पर्यावरण

ऐतिहासिक भूमाफिया पहले किसानों की हजारों एकड़ जमीन के औने-पौने सौदे करो, फिर उस पर सरकारी योजना, सुपर कॉरीडोर औद्योगिक क्षेत्र आवासीय शासकीय योजना लागू करवाकर हजारों करोड़ का खेलकर खाओ, इसलिये शिव ने अपने अनन्य गण को नगरीय प्रशासन व विकास, आवास और भ्रष्टाचार का चरम पर्यावरण विकसित करने का मंत्रालय सौंप दिया है, ताकि उनका ये अनन्य गण पूरी तन्मयता से सक्रिय रहकर अपना गुणात्मक विकास करें। हर नगर में कैलाश नगर, आकाश नगर बनाकर शिवधामों में शिव को अगले 5 वर्षों तक विराजित करा सके, ताकि शिव सत्ता की भांग में मस्त रहे।

मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा : स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, आयुष, गैस त्रासदी एवं सांसदीय कार्य

मप्र लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में न केवल केन्द्र व राज्य का लगभग रु. 30000 करोड़ से ज्यादा का आवंटन वरन अंतर्राष्ट्रीय, स्वास्थ्य संगठनों का भी धन प्राप्त होता है, इस विभाग में केन्द्र और राज्य की 84 योजनाओं में धन आता है, जिसकी खुली लूट, वसूली और भ्रष्टाचार की सामायिकी प्रदेश देश और विदेश में फैलजाती है। यथार्थ में डॉक्टर जन स्वास्थ्य का डॉक्टर शैक्षिक और मानसिक रूप से हो न हो, पर वह लूट, वसूली भ्रष्टाचार, भय और भ्रम से कमाई का डॉक्टर तो अवश्य है, स्वाभाविक है मंत्री उन डॉक्टरों के नर उत्तम है। फिर इस धन को निजी चिकित्सालयों को शासकीय योजनाओं के अंतगर्त धन लुटाने, कमीशन खाने, उनकी बीमारों को लूटने खाने, उसमें वसूली करने आदि में इनका हिस्सा पहुंचाता है। फिर पूरेप्रदेश के 51 जिलों में मात्र 38 मु. चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी उनमें से भी 22 प्रभार में इसलिये बैठाये गये हैं। ताकि रु. 200 करोड़ प्रतिमाह की वसूली प्रति माह तक बनी रहे, फिर ड्रग ट्रायल जिसे केन्द्रीय और राज्य सरकारों के मंत्री, सचिव, संचालक तक मोटी कमाई का जरिया मानते हैं। केन्द्रीय राज्य सरकारों यहां तक कि सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के 125 करोड़ द्विपादीय स्तनपाई जानकारों पर ड्रग ट्रायल को एक लाइन का आदेश देकर रोका नहीं वरन हजारों रु. ड्रग कंपनियों से डकारने वालों ने सैकड़ों दलीले दी, चिकित्सा शिक्षा में जालसाजियों, मुन्नाभाइयों की नौटंकी पाठक समाचार पत्रों और टीवी चैनलों देख ही रहे हैं। आयुष विभाग में सरकार ने सुविधाएं तो ढेर सारी दे रखी है। परन्तु उस बजट से कागजों पर लेटे मरीजों की चिकित्सा ही होती है।

कुंवर विजय शाहः खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण

इनका इतिहास, अय्याशी, लूट और जालसाजियों के साथ ही हिदायत बतमीज और खंडवा हरसूद में गुंडागर्दी का भी रहा है। बस सत्ता पक्ष के विधायक होने व मंत्री बनने के कारण इन पर मुकदमें दर्ज नहीं हुये, इसी कारण से पूर्व में इन्हें मंत्री पद से हटाया गया था, शिवराज पर दबाव के चलते इन्हें विधायक का प्रत्याशी बनाया गया और जीतने पर मंत्री पद भी देना पड़ा, इनके मंत्री बनने से राशन दुकानों राशन मिट्टी के तेल की कालाबाजारी बढ़ेगी, पेट्रोल-डीजल पंपों पर मिलावट और कम नाप से जनता को खुले में लूट और वसूली बढ़ेगी, यहां बैठे भ्रष्ट महीनाखोर जिला, खाद्य व नागरिक आपूर्ति अधिकारी से लेकर निरीक्षक तक दोनों हाथ से बटोरने के लिये दुकानदारों, पंपों, गैस डीलरों को जनता को लूटने की खुली छूट देकर, मंत्री की सेवा करेंगे।

मंत्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेनः किसान कल्याण एवं कृषि विपणन

पूर्व में बिसेन के पास लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग था, जहां प्र.स.स. से लेकर प्रमुख अभियंता,मुख्य अभियंता,अधीक्षण यंत्रियों से लेकर उपयंत्रीयों और हैंडपंप सुधारक तक केन्द्र और राज्य की योजनाओं में भारी भ्रष्टाचार मचा ही रहा। अब जबकि बिसेन किसान कल्याण एवं कृषि विपणन के मंत्री है। रु. 30000 करोड़ से ज्यादा का बजट राज्य और केन्द्र सरकार का मिलता है, जिसका 50प्रश से ज्यादा पैसा केवल कांगजों के खेतों पर आंकड़ों की फसलें पैदा करता है, किसानों को जो लाभ मिलना चाहिये तो कृषि विस्तार अधिकारी, एसएडीओ, एडीओ, उपसंचालक, संयुक्त संचालक कृषि और संचालक कृषि, सचिव, प्रधान सचिव, मंत्री और मुख्यमंत्री तक डकार लिया जाता है। लो. स्वा. यां. में बढ़ते भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की तो दूर उल्टे ही वहां के भ्रष्ट, आपराधिक, जालसाज अधिकारी डामोर को बचाते रहने एक ही पद पर एक ही अधिकारी जैसे का.यं. चैतन्य रघुवंशी जैसे को पालने-पोसने का ये जिम्मेदार सभी उपसंचालकों को जो हर वर्ष रु. 5 से 8 करोड़ डकार जाते है। संचालक तक कृषि डी.एन. शर्मा जैसो का पालन कर अपना हिस्सा डकारता रहेगा।

मंत्री उमाशंकर गुप्ता : उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल, विकास उन्नयन

पूर्व के गृह मंत्री रह चुके उमाशंकर गुप्ता के कार्यकाल में प्रदेश औषधि, हथियारों की मंडी, आतंकवादियों, ड्रग तस्करों, खदान भूमाफियाओं का अड्डा इन्हीं के संरक्षण में बना। सट्टा, मटका, वर्ली, क्रिकेट, जुआ घरों, आदि भी महीना बांटकर खूब फले-फूले, हर नगर में हत्याओं और बलात्कारों का भी बाढ़ आ गई। पुलिस की शिकायती 100 नं. भी 90 प्रति. सेवा में नहीं लाइने व्यवस्त है, आउट ऑफ रेंज, सुनाता रहा, ताकि अपराध ही दर्ज नहीं और ये इन सब अपराधियों का महीना डकारते रहे। अब जबकि उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास उन्नयन के मंत्री है। गुप्ता जी चाहे तो प्रदेश में तकनीकी शिक्षा और उच्च शिक्षा में गुणात्मक सुधार कर प्रदेश के युवाओं का भविष्य संवार सकते है। परन्तु बनिया बुद्धि के चलते कदम-कदम शिक्षा में मचे लूट, भ्रष्टाचार में से हिस्सा ही बटोरेंगे।

मंत्री कुसुम महदेले : पशुपालन, मछुआ कल्याण एवं मतस्य विकास, उद्यानिकी व खाद्य प्रसंस्करण, कुटीर एवं ग्रामोंद्योग, विधि एवं विधायी कार्य

पशुपालन विकास विभाग में रु. 2500 करोड़ का बजट जो कि कागजों पर ही हजम कर लिया जाता है, वहीं हाल मछुआ कल्याण एवं मतस्य विकास विभाग का भी है, जहां रु. 1000 करोड़ से ज्यादा का बजट भी केवल कागजी तालाबों में विभिन्न प्रजाति की आंकड़ों की मछलियां ही पैदा होती है। उद्यानिकी व खाद्य प्रसंस्करण विभाग में भी केन्द्र और राज्य का नियोजित और अनियोजित लगभग रु. 3000 करोड़ से ज्यादा का बजट कागज के उद्यानों पर ही जड़ी बूटियों से लेकर फल-फूल, सब्जियों के बढ़े-चढ़े आंकड़ों की पैदावार करता है, सारा धन वहां बैठे बाबुओं से लेकर सहायक व उप संचालक उद्यानिकी ही हजम कर जाते हैं। हरामखोरों को सूचना के अधिकार में जानकारी भेजने पर संचालक स्तर तक सिवाय उन्हें सीधे जवाब देने के कुछ नहीं कहताहै, शासकीय उद्यानों पर कॉलोनी कट रही है। उद्यान उजाड़ पड़े हुये है। टपक बूंद और सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं का पैसा न केवल इंदौर, देवास, उज्जैन, धार, झाबुआ, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर में वरन मप्र के सभी 51 जिलों में डकारा गया। मंत्री महोदया को बहुत कुछ करने का मौका दिया है, परन्तु न तो ज्यादा शिक्षित है, प्रशासनिक क्षमता में है, जो वो कुछ करेंगी, बस पाइप लाइन और भ्रष्टाचार का पैसा जो कुल रु. 500 करोड़ तक हो सकता है, हजम करके समय व्यतीत करेंगी।

मंत्री यशोधरा राजे- वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार, सार्वजनिक उपक्रम,खेल एवं युवक कल्याण धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व

ग्वालियर, राजघराने और स्व. विजयाराजे सिंधिया की ये पुत्री इन सारे विभागों का कोई खास भला नही कर पायेगी। जबकि प्रदेश में 25 लाख से ज्यादा बेरोजगारों को जो उच्च शिक्षित है। उनके रोजगार के लिये उद्योगों का विकास करना अत्यंत आवश्यक है, अधिकांश प्रदेश सरकार के सार्वजनिक उपक्रम या तो बंद पड़े हुये है, या उनकी हालत दयनीय है। दूसरी और केन्द्र सरकार और सर्वोच्च न्यायालय की मंशानुसार मप्र राज्य परिवहन विभाग को पुनः विकसित करना अति आवश्यक है, परन्तु परिवहन माफिया जनता से लूट को न तो बंद करना चाहता है न सुविधाये देना, साथ अधिकांश सार्वजनिक उपक्रमों और उनकी संपत्तियों को या तो पूंजीपतियों को सौंप दिया गया है, या सौंपने की तैयारी है। मंत्री महोदया से न तो विकास की उम्मीद की जा सकती है, न इन सब विभागों में भ्रष्टाचार के नियंत्रण की जिससे अधिकांश उद्योगपति प्रदेश में उद्योग लगाने से बिचक जाते है।

मंत्री राजेन्द्र शुक्ल- जनसंपर्क, ऊर्जा, खनिज साधन, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा

मुख्यमंत्री शिव ने अपने इस गण को जो प्रदेश का कुख्यात, खदान माफिया होने के साथ ही बिजली माफिया भी है। जनसंपर्क विभाग सौंपने के साथ पुनः पूरे प्रदेश की खदानों और खनिजों के दोहन का प्रभार ही सौंप दिया क्योंकि इस पंचवर्षीय में जो लूट और खोद-बेच लो अब सत्ता मिली न मिली इसी की दलाली में सिंगरौली में रिलायंस पावर प्लांट लगा रहा है उससे बिजली खरीदी में प्रति यूनिट रु. 1 रु. का भी कमीशन मिला तो हर घंटे करोड़ों रु. की आय होगी, इसलिये प्रदेश के विद्युत ऊर्जा संयंत्रों जो सारणी, चचाई, वीरसिंगपुर पाली आदि में है। कभी कोयले की कमी बताकर, कभी खराब कोयला, कभी संयंत्र पुराने होने के नाम पर बंद करवा दिये गये, राष्ट्रीय जल विद्युत निगम, से इंदिरा सागर, ओंकारेश्वर की 51 प्रश विद्युत की अनुबंधित शर्तों पर खरीद के साथ बची हुई 49 प्रश विद्युत को भी बाजार दर पर खरीदने से मना कर चुनाव के पहले 6 माह में रु. 25000 करोड़ से ज्यादा की बिजली खरीदी की जाकर रु. 5000 करोड़ का कमीशन डकारा गया, दूसरी और सभी वितरण, उत्पादन और परिषण कं. में चुन-चुन कर भ्रष्ट बैठाये गये जो केवल लूट और वसूली कर एक तरफ हजारों करोड़ रु. का कमीशन दे सकें, तो दूसरी तरफ कं. को घाटे में दिखाकर बिजली की कीमतें बढ़ाकर जनता से लूट और वसूली कर सके।

मंत्री ज्ञानसिंग- आदिम जाति एवं. अनुसूचित जाति कल्याण

इस विभाग में कैसी जालसाजियां की जाती है। पाठक वर्षों से पढ़ रहे है। इस मद में केन्द्र व राज्य सरकार आदिम जाति व अनु. जाति विकास के नाम पर लगभग रु. 25000 करोड़ से ज्यादा आवंटन किया जाता है। जिसका अधिकांश पैसा सहा. आयुक्त जिला आदिम व अनु. जाति द्वारा 50 प्रतिशत से ज्यादा हजम कर लिया जाता है, जिसका 5 से 10 प्रतिशत मंत्री के खाते में आयेंगे। इसका 25 प्रतिशत शिव के खाते में जाएगा। यहां छात्रवृत्तियों, आदिम व अनु. जाति के छात्रावासों, उनके निर्माण रखरखाव के नाम जिलों में 25 से 100 करोड़ रु. तक डकारे जाते है। जिसमें जिलाधीशों से लेकर आयुक्त, उपायुक्त, सचिव व प्रधान सचिव तक खुलकर बंदरबांट की जाती है, आदिवासी जिलों और विकास खंडों में यह राशि अरबों रु. तक की जाती है, जिसमें इंदौर संभाग के 6 जिलों जिसमें खंडवा, खरगोन, धार, झाबुआ, बड़वानी, अलिराजपुर में विभिन्न मदों में हर जिलों में जिसमें ग्रामीण विकास, कृषि, उद्यानिकी, स्वास्थ्य, शिक्षा के नाम पर लगभग रु. 2000 से 3000 करोड़ प्रतिवर्ष मिलता है, जिसका 25 प्रश वास्तविक लक्ष्य पर खर्च न होकर हजम कर लिया जाता है। मंत्री ज्ञान सिंग भी रु. 400 करोड़ विभिन्न मदों से प्राप्त करेंगे।

मंत्री अंतरसिंह आर्य- श्रम, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जाति कल्याण

विश्व व्यापार संगठन के दबाव में बहुत सारे श्रम कानूनों को या तो बदल दिया गया है, या अब उनका पालन नहीं किया जा जाता है। ताकि बहुराष्ट्रीय और राष्ट्रीय कं. श्रमिकों का चहुदिशा शोषण कर सकें, दूसरी और श्रम कानूनों के फेर से बचने, ठेका श्रमिक अधि. में श्रमिकों को जानवरों से ज्यादा कुछ नहीं समझा जाता। अब अंतराष्ट्रीय श्रम कानूनों में 8 घंटे का श्रम, साप्ताहिक अवकाश आदि का कोई मूल्य नहीं रह गया है। यथार्थ श्रम कल्याण विभाग के निरीक्षकों की फौज से लेकर आयुक्त तक महीना डकार कर केवल कागजी औपचारिकतायें ही निभाते दिखते है। पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में केन्द्र और राज्य सरकारों का जो धन आता है उसमें से ही रु. 25-50 करोड़ की सालभर में आर्य जी को खुरचन मिल जाये तो ही बहुत है। मंत्रीजी के प्रशासनिक क्षमतायें हो तो कुछ कर दिखाने को तो है, पर बहुराष्ट्रीय कं. के सामने सभी नतमस्तक है। इसलिये केवल मंत्री होने का रुतबा भर झाड़ सकते है।

मंत्री रामपाल सिंह- लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय एवं राजस्व

पूर्व में भी रामपाल सिंह इसी विभाग के मंत्री थे, जीतने के बाद पुनः शिव ने अपने गण को यही बैठा दिया जो प्रधान, सचिव, प्रमुख अभियंता कहें वो कर दो अपना हिस्सा लो और चुप रहो, प्रदेश की जनता को पीने का दैनिक उपयोग के लिए स्वच्छ और स्वास्थ्य वर्धक जल आपूर्ति के लिये केन्द्र और राज्य की 10-12 योजनाओं में नगरीय योजनायें जो अधिकांश नगर निगमें, पालिकाओं के अंतगर्त है। दूसरी और ग्रामीण क्षेत्रों की परियोजनाओं के निर्माण विकास और रखरखाव योजनायें सीधे ही लो. स्वा. या. विभाग के अंतगर्त है। पर प्रदेश में जल आपूर्ति का कार्य लो. स्वा. या. ही प्रत्यक्ष रूप से देखता है, जिसमें रु. 8 से 10000 करोड़ जिसमें एडीबी आदि का ऋण भी शामिल है का बजट पूरे प्रदेश में आवंटित होता है। यहां पर प्रमुख अभियंता से लेकर सभी मुख्य अभियंता अधीक्षण, यंत्रीयों, कार्यपालन सहायक व उपयंत्रियों तक भ्रष्टाचारियों का गिरोह बैठा हुआ है। जो टैक्सियों में धन लूटने से लेकर रु. 2 लाख के टेंडर जारी कर हर संभाग में रु. 3 से 5 करोड़ हजम करता है, फिर अनाप-शनाप पाइपों, मोटरों की खरीद, बड़े-बड़े निगमों तथा इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर, रीवा आदि में सुधार और रखरखाव के नाम से भी हर वर्ष रु. 2 से 5 करोड़ हजमकर लिये जाते हैं। सूचना के अधिकार में जानकारी न देने के लिये हर कदम साजिशें की जाती हैं। मुख्य अभियंता (यांत्रिकी) सबसे ना तो आवेदन अपील, सब पीने के आदि हो गये है। मंत्री दया की निधि मारने में विश्वास रखते हैं। उन्हें प्रशासन न तो आता है न बेचारे करते है। जहां प्र.स.,सचिव, प्रमुख अभियंताओं ने कहा आंख भींचकर अंगुठा लगा देते है। इसलिये सब ही इन्हें पाकर खुश हो गये।

मंत्री माया सिंह- महिला एवं बाल विकास

इस विभाग में लूट और भ्रष्टाचार की मूल जड़ आंगनवाड़िया है। जहां 60 से 90 बच्चे पंजीकृत होते हैं। पर यथार्थ में इन आंगनवाड़ियों में 5 प्रश बच्चे भी नहीं आते। दूसरी और कई आंगनवाड़ियों के तो कई दिनों तक ताले ही नहीं खुलते, अर्थात सारी खानापूर्ति कर 90 से 100 प्रतिशत तक धन हजम कर लिया जाता है। फिर गर्भवती महिलाओं के साथ ही 5 वर्ष तक के निर्धन बच्चों की माताओं का पौष्टिक आहार आदि का वितरण भी कागजों पर ही संपन्न हो जाता है, वर्षों तक समय माया द्वारा तथ्य प्रकाशित करने के बाद अब प्रशासन ने छापामारी करना शुरू की तो मालूम पड़ा कि महीनों से आंगनवाड़ियों के

ताले ही नहीं खुलते और पूरे विश्व में कुख्यात खंडवा जिले के खालवा विकास खण्ड में कुपोषण से बच्चों के मरने पर रोक नहीं लगाई जा सकी। इसके बाद भी न ही खालवा विकास खण्ड के वि.खं. अ. आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, ए.वा.वि.यो. के अधिकारी और सुपर वाइजर के विरूद्ध कोई कार्यवाही नही की गई, इस बात से भ्रष्टाचार की लूट का अंदाजा लगाया जा सकता है। रु. 35000 करोड़ से ज्यादा के बजट में रु. 3500 करोड़ रु. मंत्री साहिबा हजम करेगी, ग्वालियर राज परिवार से जुड़ी मंत्री महोदया को ऊपरी दबाव में मंत्रालय सौंपा गया है।

मंत्री भूपेन्द्र सिंह- परिवहन, सूचना प्रोद्योगिकी, लोक सेवा प्रबंधन एवं जन शिकायत निवारण

यहां परिवहन विभाग जहां रु. 3 से 4 अरब रु.की हर दिन लूट विभिन्न माध्यमों से की जाती है, जिसमें रु. 2 अरब तो मात्र विभिन्न रूटों पर परमिट जारी करने से क्षे.प. अ. जिलाधीश,आयुक्त तक रु. 2 से 5 लाख प्रति बस ही प्रतिदिन परमिटों के नाम 200 से 300 बसों के पूरे प्रांत में होते है, हजम कर जाते है। अरविंद तिवारी जैसा निरीक्षक ही रु. 2 करोड़ प्रतिदिन केवल सड़क पर खड़े होकर वसूलता था, तो प्रदेश के 29 बड़े नाकों, 40 से ज्यादा छोटे नाकों पर क्या होता होगा, फिर लायसेंस चोरी की गाड़ियों कें पंजीयन, ट्रकों के परिमट, नई गाड़ियों के पंजीयन में 4 पहिया वाहनों के पंजीयन दो पहिया वाहनों के नाम पर ही बाबू और एजेन्ट मिलकर रु. 50 करोड़ से ज्यादा का राजस्व घाटा करवाते है, प्रतिदिन रु. 10 से 25 कारोड़ डकारे जातो है। वैसे इस लूट-खसोंट का हिस्सा सीधा मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंचता है। इसलिये मु.म. भी जानबूझकर आंख भींचकर घी पी जाते है। जो पूर्व मंत्री जगदीश देवड़ा के पास था, परन्तु बेचारे को 1 प्रतिशत भी हिस्सा नहीं मिलता था, फिर उसका दिल्ली में कोई माई बाप नहीं था, इसलिये लगातार जीतने के बाद भी मंत्री मंडल से बाहर कर दिया गया। सूचना प्रौद्योगिकी में आवंटित रु. 500 करोड़ से ज्यादा में भी बंदरबांट मची रहती है। लोक सेवा प्रबंधन में भी रु. 500 करोड़ का बजट है।

दीपक जोशी- राज्य शिक्षा मंत्री

पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के पुत्र होने के कारण इन्हें मंत्री बनाया गया है, पूर्व में भी विधायक रहते हुए दलाली के लिये कुख्यात रह चुके है। फिर स्कूली शिक्षा एवं उच्च शिक्षा में तो प्रवेश से लेकर परीक्षाओं और पास-फेल करने में कदम-कदम लूट का ही तांडव मचा हुआ है। पूरी शिक्षा चाहे पहली से 12 वी तक या कॉलेज की शिक्षा हो या उच्च शिक्षा इतनी स्तरहीन हो चुकी है, केवल धन के बदले प्रमाणपत्रों, अंकसूचियां और डिग्री बांटने की दुकाने बन चुकी है। यह व्यवसाय प्रतिवर्ष अकेले मप्र में रु. 30000 करोड़ से ज्यादा का हो चुका है। 5वी, 8वी की जिला स्तर और संभागीय स्तर की परीक्षाओं के अभाव में विद्यार्थियों को निजी, शासकीय विद्यालयों में भी आंख भींचकर अगली कक्षाओं में धकेलने के कारण 10वीं, 12वी का स्तर उत्तीर्ण विद्यार्थियों से साधारण गणित, विज्ञान व अन्य विषयों की जानकारी व ज्ञान भी नहीं होता फिर दीपक जोशी भी रु. 1000 करोड़ तक अगले 5 वर्षों में मान्यताओं, आवंटन, निर्माण कार्यों, स्थानांतरण, पदोन्नति, नियुक्तियां आदि में कमा ही लेंगे, शिक्षा में सुधार की उम्मीद बेमानी है।

राज्य मंत्री लालसिंह आर्य : नर्मदा घाटी विकास, सामान्य प्रशासन

पूरी नर्मदा घाटी यथार्थ में भ्रष्टाचार विकास प्राधिकरण है। जिसका सीधा नियंत्रण मुख्यमंत्री शिवराज के हाथों में पिछले तीनों कार्यकालों में रहा, जहां इस धूर्त शिवराज को कार्य पूर्ण करने में कभी विश्वास नहीं रहा इसे तो बस बड़े-बड़े ठेके देकर सीधा कमीशन डकारने से मतलब रहा। इसलिये ही इसने उस महाधूर्त सदस्य अभियांत्रिकीय जेआर इंगले को बनाया जो न केवल एसडीओ के कार्यकाल से भारी भ्रष्टाचार और ठेकेदारों की कठपुतली बन नाचने का आरोपी रहा वरन अपने बेवड़ेपन के कारण भी कुख्यात रहा। इसे सेवा निवृत्ति के बाद नियुक्ति देने का सीधा मतलब था काम हो न हो आवंटन लो, हमारा हिस्सा दो, जो सैकड़ों करोड़ में था, राज्य मंत्री के रूप में लाल सिंह आर्य को भी थोड़ी खुरचन मिलेगी, सामान्य प्रशासन विभाग में जरूर मंत्री को रु. 10-20 करोड़ की मासिक आय पाईपा लाइन से मैदानी क्षेत्रों में बैठे जिलाधीशों और आयुक्तों से मिल सकती है। वह भी जब ये अपनी शक्तियों का सदुपयोग कर पाये, वैसे प्रशासनिक आकाओं को चला पाना इनके बूते की बात नहीं।

मंत्री शरद जैन- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, आयुष, गैस राहत एवं संसदीय कार्य

डॉ. नरोत्तम मिश्रा पुराना घाघ मंत्री है, रा.म. के रूप मं शरद जैन को उनके ही सारे कार्यों या खुरचन में ही गुजारा करना पड़ेगा।

सुरेन्द्र पटवा- संस्कृति एवं पर्यटन

भूतपूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा के पुत्र होने के कारण शिवराज ने मंत्रीगणों में स्थान दिया, दोनों ही विभाग भरपूर मौज, मनोरंजन के साथ रु. 25-50 करोड़ क आय के योग वाले है। मुख्यमंत्री शिवराज शक्ल से तो भोले और सज्जन दिखते है, परन्तु न तो ये भोले है और न सज्जन बस जनता से शिष्टाचार करते है। अपने मंत्री परिषद के गठन में योग्यता तो कोई पैमाना ही नहीं था, ऊपरी आकाओं जो दिल्ली से लेकर रा. स्व. स. के नागपुर में बैठे है। उनके दबाव में मंत्री चुने गये और उन्हीं के दबाव में विभागों का वितरण हुआ। शिव कमाई के मामले में और भ्रष्टाचार में भी काफी घाघ हो चुका है, आप ने मु.म. शिवराज के बारे में जो टिप्पणी की थी तो वह 25 प्रतिशत बिलकुल सही परन्तु अधूरी थी,कि केन्द्र में मनमोहन तो मप्र में शिवराज की स्थिति है,परन्तु दोनों ही महाभ्रष्ट बहुराष्ट्रीय कं. के दलाल कमीशन खोर, कंबल औढ़ कर घी पीने वाले है। भ्रष्टजालसाज इंडियन एव्यूसिंग सर्विस अधिकारियों के साथ ही बड़े पूंजीपतियों टाटा, अंबानी, बिरला, आईटीसी, हिन्दुस्तान लीवर आदि की कठपुतली बन, कमीशन डकार उनके हितों, जनहितों और राष्ट्र को गिरवी करने में कांग्रेस जो अंग्रेजों की अवैध औलादें ये ही अवैध औलाद सिद्ध हो रहे है। खाद्य, वस्तुओं, खेत-खलिहान, सड़के, बिजली, पानी सब उन्हें सौंपने, बदले में कमीशन डकारने में सिद्ध होते जा रहे है।

क्या विक्रमादित्य पर...

पेज 1 का शेष

जिनके आधुनिकीकरण से हम बहुत कुछ अच्छा और शत्रुओं से भारी पड़ने लायक बंदूकों, राइफलों, टैंकों, तोपो से लेकर विभिन्न श्रेणी के लड़ाकू विमानों तक का निर्माण कर सकते थे। हमने रूसी मिग-21 जैसे फाइटर को जो 1960 में रूस ने कबाड़े में रख दिये थे। 1962 से चीन के युद्ध के बाद तो कबाड़े को सुधारकर न केवल खरीदे वरन 1962 से लेकर 2013 अर्थात 51 वर्ष उपयोग में लाये, कितनी शर्मनाक था की हम 51 वर्ष तक उसका अग्रिम पंक्ति का भारतीय संस्करण तैयार नहीं कर पाये। वही हाल मिग-23, मिग 29, सुख़ोई 30 तक के उनके कबाड़ हो चुके जहाजों को खरीदकर बड़े शान से उड़ाकर देश की रक्षा का दंभ भर रहे हैं। जबकि हमारे पड़ोसी चीन और पाकिस्तान हमसे अच्छे और अत्याधुनिक लड़ाकू जहाजों की खेप का उपयोग कर रहे है। और हमें चमकाते रहेंगे,जबकि हमारी सत्तायें चाहती है तो हमारा लोहा और साधन फ्रांस, स्वीटरलैंड, और ब्रिटेन से तकनीकी सहयोग लेकर अमेरिका और चीन से बेहतर न केवल लड़ाकू विमान पनडुब्बियां, विमान वाहक, पोत, गस्ती नौकायें अपने देश में ही बनाते। हमारी जल और वायु सेना में अधिकांश लड़ाकू विमान और जहाज विदेशों से खरीदे कबाड़ा है जो उनकी सेनाओं अपशिष्ट मान अलग कर दिये थे हमारे सत्ताधीशों ने देश में उनकी चौगुनी कीमत दिखाकर सेनाओं की आवश्यकता बताकर औने-पौने में खरीद कर हजारों करोड़ का कमीशन डकारा, इसीलिये गोर्श को को जो आईएनएस विक्रमादित्य बनाकर पेश किया गया। उसमें भी रु. 10000 करोड़ से ज्यादा डकारा गया, कुल लागत रु. 20000 करोड़ की ज्यादा का भुगतान रुस को करना दिखाया गया, इसीलिये हमारे रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री, चीन और पाकिस्तान की हर ज्यादती को छुपा कर युद्ध टालना चाहते थे कि जल, थल, वायु सेना के सारे हथियार पुराने, कमीशनखोरी में खरीदे गये है? न जाने कब, कहां और कैसे धोखा दे जाये और शत्रु हमारी धज्जियां बिखेर दे, ये बात सारे राजनीतिज्ञ और सैन्य विशेषज्ञ जानते है।

मप्र वाणिज्यकर चारों तरफ भ्रष्टों की फौज

एंटीइवेजन में चुन-चुनकर बैठाये भ्रष्ट-24 घंटे वसूली 80% हजम

बाप की जागीर समझते हैं, सु.अ. के अंतर्गत आवेदनों और अपीलें उड़ाते हैं मजाक

मप्र वाणिज्य कर विभाग में यहां बैठे अधिकांश अधिकारी जो जितने ऊंचे पद पर तह उत्ना ही धूर्त और भ्रष्ट होने के साथ ही कानून का मजाक उड़ाने और उसकी धज्जियां बिखेरने में भी विशेषज्ञ हैं। इंदौर के तीन संभागों में सूचना के अधिकार में पत्र दिये गये। जानकारी जो चाही गई थी, संभाग एक में बैठे धूर्त संभागायुक्त गोपाल पोरवाल ने चाही गई जानकारी का मात्र 10% जानकारी और संभागायुक्त अब्दुल मजीद ने मात्र 307 की जानकारी दी। इसकी जब अपील की गई तो महाधूर्त अपर आयुक्त एसएल वर्मा ने सुनवाई की। इस हरामखोर ने मोयी वसूली कर लेने के कारण ही उन दोनों उपायुक्तों को अपील में ही नहीं बुलवाया और न ही उन अपीलों के जवाब में क्या लिखित उत्तर दिए उसकी ही प्रतियां दी स्वाभाविक था, कि भेंटपूजा होने के कारण उन दोनों ने वहां बैठे बाबूओं को भेज दिया। जो सूचना अधिकार कक्ष में बैठे थे, इस बत्तमीज वर्मा ने अपना पुराना इतिहास दुहराया और अपीलों यथार्थ में पूरी तरह अमान्य कर दिया। इस वर्मा ने अपने भ्रष्टाचार हर पद पर रहते हुए बड़ी बड़ी कहानियां लिखी हैं। और करोड़ों की संपत्तियां भोपाल और इंदौर में खरीदी। अभी भी अपर आयुक्त इंदौर परिक्षेत्र में रहते हुए धड़ल्ले से अपीलें स्वीकार करते हुए मोटा लेन देन कर एक तरफ करों का पुर्नभुगतान आदेश जारी कर रहा है। व दूसरी तरफ कर भुगतान में छूट प्रदान कर दोनों हाथों से वसूली कर रहा है। इस प्रकार कर राजस्व में करोड़ों रुपए की शासन को क्षति पहुंचाई जा रही है जब सूचना के अधिकार में इस जानकारी मांगने के लिए आवेदन लगाया गया तो बिंदुवार और समयावधि के हिसाब से शुल्क देने के लिए इसीलिए लिखा गया कि यथार्थ में चाही गई जानकारी पृष्ठों के अनुसार गणना की जा रही है। या थोक के भाव में टरकाने के लिए भारी भरकम शुल्क मांगा रहा है। अपनी आदत से लाचार इस अपर आयुक्त ने वही किया, कुछ बिंदुओं की जानकारी में एक मुश्त राशि रुपए 2625 मांग की गई। अंत में यह भी लिख दिया कि कुछ जानकारी सस्पष्ट है। उपस्थित हो कर जानकारी स्पष्ट करें। जब पत्र ही समझ में नहीं आया तो रुपए 2625 किस जानकारी के लिए मांगे गए। इस पत्र का जावक क्रमांक 1086 दि. 26/12/13 है। मप्र के वाणिज्य कर मुख्यालय से अनु. जाति जनजाति के अंतर्गत कार्यरत अधिकारियों के जाति प्रमाण मूल निवासी और उमावि उत्तीर्ण होने के प्रमाण पत्रों की छायाप्रतिलिपियां पिछले 5 वर्षों से मांगी जा रही है। पर यहां बैठे धूर्तों, जालसाजों और भ्रष्टों की फौज टालती आ रही है और जानकारी देने के नाम पर केवल बत्तमीजियां की जा रही है। अब जबकि मुख्यालय के सूचना अधिकारी के रूप में बैठा उपायुक्त मीना जो स्वयं फर्जी है, कैसे दे जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी और उमावि का प्रमाण पत्र। पत्र क्रमांक 242/13 सुअ/तीन744 दि. 17/12/13 में लिखते हैं कि अत्यधिक विस्तृत जानकारी है दी जाना संभव नहीं है। कितने अधिकारी हैं ज्यादा से ज्यादा पूरे मप्र में 500 के तीन प्रमाण पत्र 500 बटा 2 प्रति पेज 3000 रुपए जबकि सहा.वा.कर अधिकारी स्तर ऊपर के तीन सौ अधिकारी भी नहीं होंगे। जिसमें से 407 फर्जी प्रमाण पत्रों पर नौकरी कर रहे हैं। कैसे दे जानकारी अर्थात जालसाजों के ये गिरोह कैसे मजाक उड़ा रहे हैं, जबकि शिकायतें ढेर सारी हैं और शिकायतकर्ता भी असली अनु. जाति और जनजाति के ही है। जो फर्जी अधिकारियों को हर विभाग में बाहर करने की गुहार लगा रहे हैं। वर्षों से इसकी जांच भी अनु.जाति, जनजाति आयोग ही करता है। वो भी चाहते हैं कि फर्जी अधिकारी कर्मचारी उनका हक मारना बंद करें तो असली वालों को आगे बढ़ना का मौका मिले क्योंकि ये फर्जी वाले ही जिस तिकड़म और जालसाजियों से अंदर आये हैं, उसी तिकड़म व भ्रष्टाचार से दोनों हाथों से अच्छे कमाई वाले पदों को हथिया कर कमाई कर लुटाते है। उन्हें मालूम है कि जब भी पोल खुलेगी नौकरी जायेगी ही इसलिये जरुरी है लूटो-खाओ न जाने सच सामने आ गये और नौकरी चली जाये। वर्तमान में मुख्यालय में पदस्थ आयुक्त अमित राठौर निहायत ही ढीला और भ्रष्ट है, अधिकतर समय मुख्यालय से गायब रहने के कारण विभागीय तौर पर भ्रष्टाचार और जालसाजियां बढ़ी हैं। जिसका फायदा जालसाज बड़ी फर्में और व्यापारी भरपूर तो उठा ही रहे हैं। संबंधित अधिकारी कर्मचारी जिसमें प्रदेश की 5 एंटी इवेजन ब्यूरो जिसमें दो इंदौर की ए और बी भी भरपूर दोनों हाथों से लूटकर उठा रही हैं।

जिस फार्म 49 पर माल बाहर से लाया जा रहा है, एक ही फार्म पर 10-12 ट्रक माल लाकर एक ही प्रविष्टि की जा रही हैं, क्योंकि इस फार्म 49 को विभागीय साइट से डाउनलोड करने पर उस पर समय और तारीख नहीं आती, इसलिये एक ही फार्म पर अलग-अलग दिशाओं से अलग-अलग माल मंगवाकर कर चोरी से रु. 50 करोड़ प्रतिदिन से ज्यादा की हानि शासन को पहुंचायी जा रही है, वह भी मात्र इंदौर में ही फिर इंदौर में ए और बी में बैठी सहा. वा.कर अधिकारियों जिसमें स.वा.क.आ. अलका डामोर प्रतिमा, सदानन्द कानूनगो, कराधान सहायकों में रोहिताश्व और सजन खत्री, बी में बैठे वा.क.अ. संध्या सिलावट, सोनकर, तोमर, स.वा.कर अधिकारी जैन, मौर्य, मिश्रा, निरीक्षक चौरे, कराधान सहायक बाबर, भाले, वैसे भाले कार्यालय में ही है। पूरी ए और बी विंग के इन अधिकारी कर्मचारियों ने अकेले इंदौर में 25 से ज्यादा स्थानों पर 50 से ज्यादा छोटे-मोटे दलाल और सूचना देने वालों का जाल बिछा रखा हैं, जो इंदौर में चारों तरफ से प्रवेश करने वाले ट्रकों की सूचनायें देता हैं और फिर अपनी बीट के अनुसार उन ट्रकों, लोडिंग रिक्शा, बसों आदि को बाहर के बाहर ही पकड़कर वसूली कर छोड़ देते हैं। इन दोनों अ और ब में अवैध वसूली करने वालों में स.वा.क.अधि. प्रोतिमा करारी, वा.क.अ. डामोर का लक्ष्य हर दिन रु. 50 हजार से लेकर रु. 1 लाख तक अवैध वसूली करना रहता है। वहीं हाल ब में दोनों स.वा.कर. अधि, व वा.क.अ. का भी हैं, इनकी आठ घंटे की सेवाओं के अतिरिक्त भी सुबह 6 बजे से एमआर 10, बाइपास, धार नाके, महू नाके, खंडवा रोड, सांवेर रोड पर वसूली करने के लिये अपने दलालों के साथ जाकर छापामारी कर वसूली करते हैं। जब सौदा बिना कार्यालय की जानकारी में पकड़े गये ट्रकों, लोडिंग रिक्शा, मिनी ट्रकों से नहीं पटता है, तब ही वह अफीम गोदाम की शोभा बढ़ाता है और उसके दरवाजे पर रखी पंजी में उसकी प्रविष्टि होती हैं, फिर सौदा पट जाता हैं तो उसमें से बिना कर भुगतान के भी प्रविष्टि काट कर बिना गेट पास के ही माल वाहक को छोड़ दिया जाता है, ये सब हर दिन का एक न एक का नियमित सिलसिला हैं, ये दोनों विंग नियमित वसूली की अवैध वसूली के चक्कर में प्रतिदिन रु. 1 करोड़ से ज्यादा की राजस्व हानि करवाने से नहीं चूकते, इस तरह रु. 5 से 10 लाख तक ये दोनों विंग नियमित हजम कर जाती हैं। लोकायुक्त की नजरों में सब हैं, परन्तु वो ठोस कार्यवाही के लिये पुख्ता सबूत और वसूली करते रंगेहाथों पकड़ने के इंतजार में हैं, वैसे यहां से भी नियमित वसूली वहां तक पहुंचाई जाती हैं, जबकि यहां पर वा.क.अ. सहा. आयुक्त से लेकर कर सहायकों तक को 6 माह से ज्यादा नहीं रखना चाहिये। जैसा के नाकों पर तीन माह से ज्यादा रखने की व्यवस्था नहीं हैं। दूसरी ओर इंदौर-उज्जैन संभाग में 15 जिलों के लिये मात्र दो विंग हैं। जबकि ऐसा होना चाहिए कि जहां संभागायुक्त बैठे हैं। व्यवसायिक लेन-देन के अनुसार एक-एक एंटी इवेजन विंग भी होना चाहिए, अभी म.प्र. में मात्र 5 विंग में से अकेले इंदौर में ही हैं। बाकी 36 जिलों के लिए 3 विंग ही हैं। भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर जो पर्याप्त नहीं है। पूर्व वित्तमंत्री के विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी रहे वाणिज्यकर अधिकारी एसडी रिझारिया, विश्वस्त सूत्रों के अनुसार राघव के वसूली एजेन्ट, स्थानांतरण पदस्थापना के लेन-देन और वसूली अधिकारी ये महाधूर्त दस वर्ष में ही वा. कर अधिकारी से अपर आयुक्त बनने की तैयारी में हैं, जबकि राघव जी की गिरफ्तारी के बाद इसकी भी गिरफ्तारी होने की खबरें आई थीं। यह जालसाज 10 वर्ष में ही ओएसडी रह कर मंत्री के साथ रहने के कारण जालसाजी सहा. आयुक्त फिर उपायुक्त बनता चला गया, जबकि उसके साथ के कई अभी सहा. आयुक्त ही हैं। साथ के वाणिज्य अधिकारी उच्च न्यायालय की शरण लेने की तैयारी में है कि वरिष्ठता क्रम में पीछे होने के बाद भी कैसे और क्यों अपर आयुक्त बनाया जा रहा है।

सरकारी अधिकारियों को टैक्सी का उद्देश्य था मितव्ययिता परन्तु

निजी टैक्सियों को किराया भी, पेट्रोल और डीजल से रु. दो अरब से ज्यादा की चोट

म.प्र. शासन ने शासकीय कार्यों को संपन्न करने के अधिकारियों को आने जाने के लिये मैदानी क्षेत्रों में सेवाओं आदि के लिये वाहनों की खरीद के लिये भारी निवेश से बचने, रखरखाव के नाम भारी भ्रष्टाचार आदि को समाप्त करने के दृष्टिकोण से 05 से ज्यादा विभागों जिसमें लोनिवि., लो.स्वा.यां., जलसंसाधन, ग्रामीण यांत्रिकीय, आबकारी, वाणिज्यकर, स्वास्थ्य, महिला बाल विकास, कृषि, उद्यानिकी वन विभाग, शिक्षा, पुलिस, जिलाधीश, संभागायुक्त कार्यालयों आदि विभागों में किराये पर टैक्सियां लगाने के लिये निजी टैक्सियां लगाने की छूट शासकीय नियमों का पालन करते हुए की गई, इसके विपरीत शासन की मितव्ययिता की मंशा को दरकिनार करते हुए अधिकांश विभागों के अधिकारिया, इंजीनियरों ने सरकार की डाल-डाल पर अधिकारियों ने भ्रष्टाचार के अनेकों रास्ते निकाल लिये और अपने मिलने-जुलने वालों, रिश्तेदारों की टैक्सियों को जिसमें लोनिवि, लोक स्वा. यांत्रिकीय, नर्मदा घाटी विकास भ्रष्टाचार प्राधिकरण, म.प्र. जल संसाधन विभागों, ग्रामीण यांत्रिकीय विभागों जिसमें इन सभी विभागों के मुख्य अभियंता, अधीक्षण यंत्रियों, संभागीय यंत्रियों, सहायक यंत्रियों ने पूरे प्रदेश के सभी कार्यालयों से देखा गया कि ये सारे जालसाज न केवल अपने पद और वेतनमान की सीमाओं के विपरीत जाकर गाड़ियों को न केवल मासिक किराया रु. 16 हजार से लेकर रु. 24500/- तक बिना टैक्सी परमिट की गाड़ियों बिना ड्राइवर टैक्सी धारक को डीजल और पेट्रोल अलग से भुगतान के माथे चुका रहे हैं।

जब आइल डीजल पेट्रोल के अलग से भुगतान और फिर गाड़ियों का भी रु. 3 लाख प्रतिवर्ष किराया चुकाया ही जा रहा है तो शासन को तो इससे कुल मिलाकर हानि ही हो रही है। तीन साल में रु. 9 लाख का किराया चुकाने के बाद भी गाड़ी मालिक की कमाई में तो शासन अपना स्वयं का वाहन खरीद सकता था। फिर ड्राइवरों का वेतन भी शासन उन्हें दे ही रहा है, तो शासन को तो दोहरी आर्थिक चोट पहुंचाई जा रही है।

सूचना के अधिकार में मुख्य अभियंता लोनिवि, जलसंसाधन, लोक स्वा. यांत्रिकीय, निचली नर्मदा परियोजनायें, नघाविप्रा. इंदौर से मांगी गई थी, इसके साथ ही मुख्य

अधिकांश विभागों में अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपनी ही कारें किराये पर देकर कर रहे कमाई

अभियंता लो.स्वा. यांत्रिकीय (यांत्रिकीय) भोपाल से मुख्य अभियंता (इंदिरा सागर नहरें) नघाविप्रा सनावद को सूचना के अधिकार में ना देकर जानकारियां मांगी गई। परन्तु मोटी चमड़ी के शूकर जिसमें मुख्य अभियंता सोनगरिया लो.स्वा.या. के जालसाज ने अपील लगाने के बाद शुल्क के लिए पत्र लिखा। मु.अ. सक्सेना (यांत्रिकीय) भोपाल जो न केवल भ्रष्ट, जालसाज है वरन् धूर्तता का परिचय देते हुए पत्र और अपील का जवान ही नहीं दिया गया। इसके विपरीत मु.अ. नघाविप्रा, नि.न.परि. इंदौर द्वारा जो आधा अधूरा जवाब दिया गया उससे ज्ञात हुआ कि रु. 600 से 800/- प्रतिदिन का भुगतान के साथ डीजल, पेट्रोल, आइल आदि का भुगतान गाड़ी चलने के अनुसार अलग से किया जा रहा है, जबकि शासन की मंशा के अनुकूल मितव्ययिता के लिये प्रति किमी के हिसाब से और गाड़ी की क्षमता के अनुसार ही भुगतान किया जाना चाहिये। जब टैक्सीयां मितव्ययिता और अनावश्यक रखरखाव के खर्चों से बचाने के लिये लगाई जा रही हैं।

तो न्यूनतम स्वीकृत टैक्सी की क्षमता, कीमत के मान से प्रति कि.मी. रु. 6 से लेकर 10 रु. और खड़े रहने पर प्रतिघंटे का शुल्क ही क्यों भुगतान किया जाता है, फिर मासिक किराया 16000/- हैं, तो कम से कम 1600 कि.मी. गाड़ी चलने पर पेट्रोल, डीजल की कीमत गाड़ी मालिक ही भुगतान करें। जबकि वर्तमान में अधिकांश विभाग रु. 16000/- से 24000/- तक किराये का मासिक भुगतान भी कर रहे हैं। पेट्रोल, डीजल और इंजिन आइल की अलग से कीमत भुगतान के साथ वाहन चालक भी सरकारी, इससे बेहतर तो शासन अपनी गायिां खरीदकर ही चलायें। उसमें कम से कम सुरक्षा के साथ तत्काल वाहन की उपलब्धता बनी रहेगी। शासकीय विभागों में लगी पूरे प्रदेश के विभागों में लगी 10,000 से ज्यादा टैक्सियां जिन पर शासन के खाते से रु. 18000/- मासिक का भुगतान किया जा रहा है, तो रु. 180 करोड़ का शासन को ही घाटा हो रहा है।

तो ये टैक्सियां लगाने से मितव्ययिता कहां हो रही हैं। फिर 80% टैक्सियां सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की ही चलाई जाकर खुला लूट और भ्रष्टाचार किया जा रहा है, यदि शासन म.प्र. के 51 जिलों में कार्यरत 100 विभागों में औसतन 2-2 टैक्सियां ही लगाई गई है। तो हर जिले में 200 और 50 जिलों में 10,200 टैक्सियां उन पर औसतन रु. 18000/- प्रति माह का किराया अर्थात रु. 220 करोड़ 32 लाख प्रति वर्ष किराये में ही भुगतान किया जा रहा है, जबकि पेट्रोल, डीजल, इंजिन, ब्रेक आइल की कीमत अलग से। यदि टैक्सियों पर किये गये भुगतान और खर्च का अलग से आडिट करवाया जाये और इनकी जालसाजियों पर वाहनधारी अधिकारियों को दंडित किया जाये तो 80% अधिकारी, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स लपेटे में आ जायेंगे।

सबसे ज्यादा जालसाजियां, नघाविप्रा के जबलपुर, इंदौर, भोपाल, सनावद में बैठे सभी मुख्य अभियंताओं से लेकर एसडीओ, जल संसाधन, लो.स्वा.यां. लो.निवि., ग्रामीण यांत्रिकीय सेवायें तक सब लपेट में आ जायेंगे, जबकि 80% गाड़ियों के किराये पर लेने, भुगतान आदि कार्यों में फर्जीवाड़ा चल रहा है। शासन को चाहिए पद, वेतनमान, कार्य की प्रकृति के हिसाब से टैक्सियां किराये पर ली जायें। जो कुल कि.मी. वाहन का प्रकार आदि के अनुसार बाजार दर पर प्रति कि.मी. वेटिंग चार्ज के साथ भुगतान किया जायें। न्यूनतम दरों पर निविदायें स्वीकृत की जाकर भुगतान किया जाये। इस प्रकार शासन अरबों रु. की बचत कर सकता है।

बलात्कारों में आड़ में, कांग्रेस कर रही जनहितों का बलात्कार

पेज 1 का शेष

जिसमें गिरोह की मुखिया इटालियन सोनिया गांधी, कपिल सिब्बल, मनमोहन, पी. चिदम्बरम ने पूरी न्यायालयीन व्यवस्था, वहां बैठे न्यायाधीशों की आतंकित करने, चमकाने, अपने हिसाब से अपने ईशारों पर नचाने के लिए, गांगुली को बकरा बनाया गया, इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान कार्यरत न्यायाधीशों पर दबाव बनाकर अपनी इच्छानुसार उसे दोषी सिद्ध किये जाने की कोशिश से देश की सर्वोच्च न्यायालय से लेकर देश के सभी उच्च न्यायालयों के, सभी सत्र और जिला न्यायाधीशों को ये अप्रत्यक्ष संदेश दिया जाता है कि हम सत्ताधीश है। हम जैसा कहें वैसा करों, हमारे कुकर्मों, जालसाजियों, भ्रष्टाचारों, गुंडागर्दी, आपराधिकता, बलात्कारों, हत्याओं पर हमारे पार्टी के सदस्यों पर, मंत्रियों, सांसदों को न केवल सजा न दो, वरन कोई टीका टिप्पणी भी मत करो। दूसरी और हिन्दू साधु-संतों तथा महामंडलेश्वर जयेन्द्र सरस्वती, प्रज्ञा साध्वी, केशवानंद, आशाराम, नारायण सांई से लेकर, कर्नल पुरोहित व अन्य सैकड़ों हिन्दुओं जो पूर्णतः निर्दोष थे, उन्हें आतंकवादी, अपराधी बनाकर पूरे देश से हिन्दुओं को चमकाने-धमकाने, दहशत फैलाने, हिन्दुओं और हिन्दुओं के प्रति नफरत पैदा करने, जो भी हमारी नेता सोनिया उसके बेटे राहुल पप्पु के खिलाफ टिप्पणी करें, सच बोले, हमारी मांग के अनुसार हमें चंदा न दें, हमारी इच्छायें पूरी न करें और हमारे विपरीत जाने की कोशिश करें, देश में ईसाईयत फैलाने में अड़चन पैदा करें, धर्म परिवर्तन से रोके, उन सबके विरूद्ध हम एसटीएफ, एटीएस, सीबीआई, क्षेत्रीय पुलिस, एनआईए व अन्य अनेकों दृष्य-अदृष्य एजेंसियों के माध्यम से हिन्दुओं के बजरंग दल, हिन्दू महासभा, विश्व हिन्दू परिषद, रा.स्व.से., साधु संतों आशाराम, रामदेव आदि पर जो भी बलात्कार, हत्या, मनी लांडिंग आदि को मुकदमों में फंसाकर बेइज्जत करना, पूरे देश में घुमा-घुमा कर झूठे सबूत मीडिया के माध्यम से प्रस्तुत करना, न्यायाधीशों पर दबाव डालकर कारागृह भिजवाना, आतंकित करने के लिये पुलिस अभिरक्षा में देकर मारापीटी करवाना, साध्वी प्रज्ञा के साथ सुरक्षा सैनिकों द्वारा बलात्कार, शारीरीक उत्पीड़न करवाना, 5 वर्ष तक पूरी तरह से बर्बाद करने के बाद सारे प्रकरणों में निर्दोष बताकर खुले में समाज के सामने खड़ा कर देना। जयेन्द्र सरस्वती के मालले में और अन्य अनेकों प्रकरणों में केवल हिन्दुओं को ही परेशान करने की, मुगलकालीन व्यवस्था का पालन कर रहे हैं। ये शूकर नीच कांग्रेसियों की फौज, इन हरामखोर जालसाजों को सत्ता चलाने, अपने कुकर्मों को छिपाने, जनता और मीडिया का ध्यान बंटाने का शगल है। पहले कांग्रेस को इंदिरा गांधी के समय से लेकर सन 2010 तक अपने कुकर्मों को छुपाने, जनता का ध्यान बांटने, मीडिया को छापने दिखाने के लिए हिन्दू मुस्लिमों के बीच दंगा करवाने, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और मुम्बई से लेकर आसाम-मिजोरम तक आतंकवादी हमले करवाने, जनता को मरवाना और उस पर अपने घड़ियाली आंसू बहाना, अपनी सत्ता चलाने का हथियार था। जब समय माया ने अकेले ही इन तथ्यों को सामने रखकर अपनी समय माया डॉट कॉम और इसके पूर्व करप्शन टू इंडिया की साइट पर चढ़ाकर पूरी दुनिया के मीडिया, दूतावासों जिसमें अमेरिका के व्हाइट हाऊस से लेकर सीएनएन, बीबीसी आदि को यथार्थ ईमेल पर भेजे गये, तो कांग्रेस ने सटीक, सुलभ और सरल हथियार बलात्कार को जिसमें हिन्दुओं में अत्याधिक प्रतिष्ठित साधु, संतों को शिकार बनाना शुरू कर दिया, उन्हें हत्या, बलात्कारों के माध्यम से अपनी सत्ता के मद में पहले उनसे चंदा मांगा जाता है वसूली की जाती है, जो देने से मना करता है, उनके विरूद्ध मुंह खोलता है, या उनकी अन्य सभी प्रकार की इच्छाये पूरी नहीं करता है, उन्हें कैसे तबाह किया जाता है यह जनता टीवी चैनलो, समाचार पत्रों में पिछले कई वर्षों से देख रही है। इसके लिये ये शातिर धूर्त भेड़िये, सेना के कर्नल पुरोहित को नीलाम कर पूरे देश की तीनों सेनाओं के हिन्दू अधिकारियों का मनोबल तोड़ने से नहीं चूकते, जबकि सेना के अधिकारी वह भी कर्नल रैंक का हिन्दू संगठन के लिये काम करने की तो दूर उनके बारे में सोचते भी नहीं, फिर क्या थल सेना का प्रबंधन इतना मूर्ख और कमजोर, नाकारा और निकम्मा होता है, उसकी अपनी खुफिया और मिलट्री, पुलिस क्या घास काटने के लिये बैठी होती हैं, उनका काम ही अपने अधिकारियों,कर्मचारियों पर निगाह रखना, सेना के क्षेत्रों में आने-जाने वालों, कर्मचारियों-अधिकारियों पर निगाह रखना, सेना के क्षेत्रों में आने-जाने वालों कर्मचारियों, अधिकारियों से मिलने-जुलने पर सतर्कता व सेना की गोपनीयता बनाये रखना इन सबके विपरीत ये ब्रह्मण कुल का सैन्य अधिकारी क्या राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होकर अपना, अपने खानदान का, अपनी सेना और साथियों की बदनामी कर सकने की जुरूत कर सकता था, पर कांग्रेस को इससे क्या उसे तो नीचता दिखाकर अपनी सत्ताधीश होने का अहं पूरा करना था, जिस देश का सिख प्रधान मंत्री लाल किले की प्राचीर से गणतंत्र दिवस पर अनने राष्ट्र और विश्व की जनरल के नाम संदेश में कहें कि इस राष्ट्र के संसाधनों पर मुस्लिमों का पूर्वाधिकार है, उसे अपने गुरू गोविंद सिंग और उनके पंज प्यारों की कुर्बानी सिख धर्म का अपमान करने से न चूका है, उसकी नीच मानसिकता की व्यक्त करने में शब्द ही बेबस नजर आने लगे। महंगाई बढ़ाने के अक्रोश को जो बलात्कारों की आड़ में, मीडिया पैसे बांटकर 24 घंटे बलात्कारों के समाचारों को चलवाकर दंगे फसाद करवाये जब मीडिया और जनता का ध्यान उन बलात्कारों की खबरों में उलझा हो तो सीधे ही पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाकर और महंगाई बढ़ाने से न चूके। मीडिया के भूखे लालची भेड़ियों को कांग्रेस टुकड़े डालकर अपनी तरह से नचाकर, अपने कुकर्मों, महंगाई बढ़ाने,कमीशन खाने, अपने भ्रष्टाचारों की खबरों पर से ध्यान बटाने के लिए जिन बलात्कारों की खबरों को तिल का ताड़ राई का पहाड़ बनाकर 24 घंटे सारी चैनल एक ही खबरों की पुनरावृति करती रहती है, उन खबरों का 5 से 15 वर्ष के युवा होते लड़के -लड़कियों की मानसिकता पर क्या असर पड़ता हैं, कभी इन कांग्रेसी और मीडिया के धूर्तों ने सोचा, कि उन बच्चों के मानस पर क्या खौफ छाता है, फिर सारे हिन्दू साधु-संत, साध्वियों से लेकर न्यायाधीश तक ही हत्यारे और बलात्कारी और चरित्रहीन होते हैं। क्या ये इटालियन पोप की धमकी जिसमें उसने कहा था कि 21वीं शताब्दी में ईसाईयत पूरे एशिया पर हिन्दूओं और बौद्धों को समाप्त करके छा जायेगी, के षड्यंत्रों के परिणाम स्वरूप सोनिया गांधी और उसकी कांग्रेस ही करवाती है, इस एक तीर से वह कई निशाने साधती है।

आश्चर्य तो इस बात का है, कि इन सब कांग्रेस की जालसाजियों हिन्दुओं के साधु, संतों, साध्वीयों की हत्या, बलात्कार, आतंक विधियों में जबरन प्रकरण बनाये जाते है। सारी चैनलों को पैसे बांटकर उनकी सामाजिक मान प्रतिष्ठा, मर्यादाओं की धज्जियां बिखेर कर तार-तार कर दिया जाता है। आशाराम, रामदेव ने जब सोनिया और उसके बेटे की लूट-खसोंट के बारे में सार्वजनिक मंचों से बोलना शुरू किया उनके द्वारा मांगा गया अरबों रु. का चंदा नहीं दिया तो आरोपों के इतिहास बनाये जाने लगे, हर कदम अपमान बलात्कार सिद्ध किये जा रहे है। साध्वी प्रज्ञा को 5 वर्ष जब पूरी तरह अस्मत सरेआम जेलों में नीलाम की गई, हत्या के, आतंकवाद, बम विस्फोटों के आरोप में देश की अनेकों जेलों, न्यायालयों में घुमाया गया तो अंत में निर्दोष करार दे दिया गया, पर कोई हिन्दू संगठन, भाजपा, आरएसएस, शिव सेना, विहीप, बजरंग दल कुछ नहीं बोला। वही हाल सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालयों जिला एवं सत्र न्यायालयों द्वारा अपने कर्तव्यों का निष्ठा से पालन कर कांग्रेस के कुकर्मों के विरूद्ध फैसले दिये गये, तो उसने जस्टिस गांगुली को छेड़छाड़ करने के आरोप लगाकर पूरे देश की न्यायालयीन व्यवस्था को आतंकित किया जा रहा है, ताकि भविष्य में कोई भी फैसला कांग्रेस के विरूद्ध न दिया जाये परन्तु सभी राजनैतिक पार्टीयों जिसमें सबसे भाजपा इस मुद्दे पर भी सब जानकर मौन है। साथ ही भारतीय विधिक परिषद, राज्यों की, जिलों की अधिवक्ता परिषदें और संघ क्यो मौन हैं। हिंसी को न देश की, देश की जनता, न्यायालयों में विश्वास और राष्ट्र की जनता के हितों के पनपते आक्रोश की चिंता नहीं है। यही कारण है कि से कांग्रेसी गिद्ध अपने तरह से देश को, देश की जनता को, संसाधनों की नोच बैच और गिरवी रख रहे हैं। सब मुंह में दही जमाये अपने स्वार्थों की सिद्धी में लगे।

साप्ताहिक समय माया

बहुतों को बचा रही एसटीएफ, अपराध शाखा और पुलिस

व्यापमं में 1985 से हर कदम, हर परीक्षा में जालसाजियां भ्रष्टाचार

मात्र पीएमटी में ही नहीं पीईटी, पीएटी व शास. सेवाओं में भी जालसाजियां हुई

भोपाल। हाल ही में आये चिकित्सा पूर्व प्रवेश परीक्षा घोटाले में सामने आये कांडों में व्यापमं के वर्तमान अध्यक्ष और संचालक और परीक्षा नियंत्रक के साथ ही वहां बैठे चपरासी और बाबु तक दलाली के धंधे में लिप्त है। साथ ही भोपाल के मप्र शासन के मंत्रालयों से लेकर सरकारी विभागों के सैकड़ों कर्मचारी अधिकारियों जिन की पहुंच व्यापमं के कार्यालय तक है, वो भी गाहे-बगाहे फर्जी प्रवेश में दलाली के ये खेल करके पैसा कमाते रहे है।जिसमें 1985 से लेकर पक्ष-विपक्ष में बैठे मंत्रियों तक की पहुंच से न केवल चिकित्सा विज्ञान वरन दंत चिकित्सा, फार्मेसी प्रबंधन, कम्प्यूटर, इंजिनियरिंग, कृषि आदि में तब से लेकर अभी तक हर वर्ष हजारों फर्जी प्रवेश होते रहे हैं।

जिसमें प्रदेश के अधिकांश बड़ी कोचिंग संस्थानों ने अहम भूमिका निभाकर अरबों रु. की कमाई की है, परन्तु आश्चर्य का विषय है कि अभी तक पूरी एसटीएफ केवल चिकित्सा महाविद्यालयों और कुछ सरकारी सेवाओं में भर्ती परीक्षाओं तक ही केन्द्रित रही है, जबकि यह संस्थान अपनी स्थापना से ही अपने फर्जी प्रवेशों और भर्तियों के लिए कुख्यात रहा है। जहां तक पैसे का सवाल है, पैसा सबसे खाया जिसकी जहां तक जमावट हुई नेताओं, मंत्रियों, आईएएस अधिकारियों से लेकर उच्च शिक्षा, तकनीकि शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, व्यवसायिक पाठ्यक्रमों से लेकर भर्ती प्रक्रिया में सिपाहियों और उप निरीक्षकों जिसमें आईपीएस राजस्व निरीक्षकों, पटवारियों खाद्य एवं औषधि निरीक्षकें, शिक्षा निरीक्षकों, शिक्षा कर्मियों व अन्य सभी विभागों में निरीक्षकों की भर्ती का कार्य व्यापमं ने किया। सभी ने लेन-देन करके ही नियुक्तियां पाई, फिर परीक्षा में उत्तीर्ण करवाने के बाद साक्षात्कार में भी खुलकर पैसे का ही खेल था वहां भी पैसा डकार गया।

दूसरी और प्रदेश के 350 से ज्यादा अभि. यांत्रिकीय महाविद्यालयों, 30 से ज्यादा दंत चिकित्सा, 500 से ज्यादा प्रबंधन और कम्प्यूटर 300 से ज्यादा फार्मेसी कॉलेज डिग्री बांटने वाले महाविद्यालयों में प्रवेश परीक्षा में जालसाजियों,भ्रष्टाचार, लूट, वसूली का खेल चलता रहा है। पर प्रदेश की सभी सत्ताये अपना पैसा हजम कर जानबूझकर आंख भींचकर शांत बैठी रही, अधिकांश कांग्रेसी, सत्ताधीश, भाजपाई सत्ताधीशों के साथ अधिकांश आईएएस अधिकारियों के पुत्र, पुत्रियों, भाई,भतीजों, दामादों, बहुओं की सरकारी सेवाओं में चयन व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में चयन में खुलकर जालसाजियां की गई है। फिर क्या मप्र में केवल अरबिंदों चिकित्सा महाविद्यालय की भर्ती में ही जालसाजियां और फर्जीवाड़ा हुआ, जबकि अरबिंदों के विनोद भंडारी के इस चिकित्सा महाविद्यालय सभी हल्को में निर्माण से लेकर संचालन तक मप्र के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्गी दानव का धन लगा होने की चर्चाए थी, उज्जैन के गार्डी मेडिकल कालेज, भोपाल के पीपुल्स, इंदौर के इंपेक्स मेडिकल कॉलेज में भदौरिया का कहा जाता है, आखिर उसके पास इतना पैसा कहां से आया जबकि पूरी भाजपा के अदने से कार्यकर्ता से लेकर दिल्ली तक बैठे सभी राजनीतिज्ञ और अधिकारियों के अनुसार इसमें भाजपा के पूर्व और वर्तमान मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का धन विशेषी है।

इन्हीं की महीमा का परिणाम है कि, यहां पर दे.अ. विश्व विद्यालय के चिकित्सा महाविद्यालय केन्द्र सरकार के धन से बनने वाले श्रम मंत्रालय द्वारा बनाये जाने वाले कर्मचारी भविष्य निधि के चिकित्सा महाविद्यालयों को नहीं बनने दिया जा रहा। ईपीएफ के इस चिकित्सा महाविद्यालयों की अनुमति को प्रदूषण मंडल ने अटका रखा है, तो दे.अ.वि.वि. के महाविद्यालयों इंदौर जिलाधीश कार्यालय में जमीन आवंटन से लेकर अन्य परेशानियां खड़ी की जा रही है।

प्रदेश में कार्यरत 350 से ज्यादा अभियांत्रिकीय और 400 के लगभग भेषज 500 से ज्यादा प्रबंधनप और कम्प्यूटर महाविद्यालय जो कि निजी क्षेत्र में चल रहे है। जिसमें प्रदेश की भाजपा कांग्रेस के साथ आईएएस, आईपीएस, आईएफएस व राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों, मंत्रियों और नेताओं के कॉलेजो में है, वो भ्रष्टाचार का ही धन, आखिर क्यों मु.म. शिवराज और साथ ही आयकर विभाग एसटीएफ क्यों सब चुप है। जहां प्रवेश से लेकर, छात्रावास, पुस्तकें, शिक्षण शुल्क, अग्रिम सतर्कता शुल्क, प्रयोगशाला शुल्क, खेल गतिविधि शुल्क, प्रायोगिक परीक्षा, बस किराया आदि से लेकर परीक्षा शुल्क, पास करवाने, मेरिटों में आने तक के हर शुल्क के नाम पर लूट-खसोट वसूली की जाकर करोड़ों रु. की अवैध कमाई की जा रही है, जबकि अधिकांश व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के महाविद्यालयों में आधारभूत संरचना जिसमें विद्यार्थियों के बैठने से लेकर, खेल का मैदान, पुस्तकालय, प्रयोगशालाये आदि की सुविधा तक भी पूरी नहीं, पढ़ाने वाले विषय विशेषज्ञों की बांट तो बहुत दूर की कोढ़ी है, ये सभी निजी महाविद्यालय यथार्थ में विद्यार्थियों के जीवन से खिलवाड़ करते हुये केवल डिग्री और डिप्लोमा बांटने वाली चाय पान की दुकान बन चुके हैं। इन सबको मान्यता देने वाली भारतीय चिकित्सा परिषद, अखिल भारतीय तकनीकी की शिक्षा परिषद, प्रदेश के अधिकांश शासकीय, विश्वविद्यालय जिनसे इनकी मान्यता सबंधित होती या दी जाती है। सब करोड़ों रु. का धन लेकर आंख भींचकर दे दी जाती है। जिसके हजारों प्रकरण पूरे भारत के अखबारों में आये दिन प्रकाशित होते रहे है। मप्र के पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा ने भी इसी सबके चलते अपना एक तकनीकि विश्वविद्यालय सिरोंज के पास सरकारी अवैध जमीन पर खड़ा कर लिया, ज्वलंत प्रश्न यह है कि ईमानदारी का ढोंग करने वाले मुख्यमंत्री अब जब तीसरी बार सत्ता में आ चुके हैं और प्रशासनिक कसावट, पारदर्शिता और ईमानदारी की बात कर रहे है। क्या इस शिक्षा की इन जालसाज दुकानदारीयों और दुकानदारों पर अंकुश लगा पायेंगे, क्या एडीजी चिकित्सा के शिक्षा के इतर व्यापमं में हुये हर कदम की जालसाजियों को उजागर कर पूर्व वर्तमान मंत्रियों नेताओं के साथ आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, सेवा अधिकारियों पर हाथ डाल सकेंगे जो कालेधन के नियोजन से कई गुना ज्यादा काला धन प्रदेश के लाखों होनहारों के लूटकर केवल कागजी डिग्रीयां बांट रहे है। नई चुनकर आई भाजपा की सरकार से भ्रष्टाचार के विरूद्ध कोई ठोस कार्यवाही की उम्मीद करना, अपने मंत्रियों और विधायकों के विरूद्ध एक तो जांच ही नहीं होने देंगे, ज्यादा दबाव में जांच करवा ली गई तो उनके विरूद्ध न्यायालय में चालान पेश करने की अनुमति ही नहीं दी जायेगी, फिर नये मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा भी पुराने भ्रष्ट है। धीरे-धीरे सभी जालसाजियों और घोटालों की फाइलें धूल के ढेर में दबा दी जाएगी।

आधार कार्ड समंको से हजारों करोड़ की कमाई

सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की धज्जियां उड़ा आतंकित कर रही तेल कंपनियां

टीवी, अखबारों, मोबाइल पर दृष्य व श्रव्य विज्ञापनों से धमकाया जा रहा है जनता को, सरकारें बहुराष्ट्रीय कं. के इशारों पर नाच रही, जनता की हर जानकारी एकत्रकर बेंचने को बेताब

राष्ट्र की केन्द्रीय सत्ता में बैठी कांग्रेस और उसके सप्रग के गिरोह के सदस्यों जिसमें राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी महाधूर्त शरद पंवार ने कृषि मंत्री रहते हुये राष्ट्र के खाद्यान्नों तथा गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का आदि तिलहनों, मूंगफली, सरसों, तिल, अलसी, दलहनों, तुअर, उड़द, मूंग, मसूर आदि के, सब्जियों आलू, प्याज, टमाटर, भिंडी, लोकी, करेले, टिंडे, मटर, मसालों- मिर्ची, हल्दी, धनियां, जीरा, राई, सौंफ, फलों- आम, अमरूद, केले, पपीता, नारंगी नारंगी आदि के मूल प्रजाति के बीजों को अरबों रु. का कमीशन डकार कर पहले विदेशी बहुराष्ट्रीय कं. को बेंच कर उन्हें सौंप दिया। उन्हें अपनी खोज, अपना आविष्कार, बनाने का अवसर प्रदान किया, फिर उनके बीजों का बीटी हायब्रीड, अनुवांशिकीय परिस्कृत कर, फिर उन बीजों को भारत में अपना मोटा कमीशन अरबों रु. डकार कर भारत में बेचने की पूरी छूट दे दी है। इन सब कार्यों को संपन्न करने में लगा और भारत के किसानों, कृषि मंत्रालय के सचिवों और अधिकारियों के भ्रष्टाचार कृषि महाविद्यालयों, कृषि विद्यालयों व्याख्यालायों द्वारा इस घोर विनाशलीला में लाखों किसानों को अपनी जीवन लीला समाप्त करने के बाद भी न तो किसान संगठनों कृषि विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, केन्द्र और राज्यों के कृषि मंत्रालयों की आवाज भी नहीं निकली। बेशक कुछ संगठनों ने बीटी कपास और बैंगन के दुष्प्रभावों पर आवाज उठाई, पर उससे कांग्रेसी गिद्धों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी, और अब दलहन, तिलहन खाद्यान्नों के बीजों से खरबों रु. प्रतिवर्ष का कमीशन हजम कर अरबों का कमीशन सत्ताधीशों को बांटा जाता है। किसानों की जमीनों पर कब्जे के लिये उन्होंने खेतो पर काम करने मजदूरों को खेतों पर काम न करे इसलिये मनरेगा लागू करवा कर किसानों को मजदूरों के अभाव में खेती न कर पाने के कारण, किसानों से लाखों हेक्टेयर जमीने आईटीसी ने मार्च 13 तक ही देश के अनेकों राज्यों में लगभग 20 लाख है। जमीन हथिया ली थी, धीरे-धीरे हर क्षेत्र को गिरवी करने बेचने का यह सिलसिला पूरे देश की कृषि भूमियों को हथियाने के लिये बहुराष्ट्रीय कं. को ठोस समंकों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए चिदम्बरम ने अपने परम जालसाज मित्र नीलकेणि को रु. 700 करोड़ का ठेका पूरे देश की जनता का आधार कार्ड बनाकर, हर गांव, नगर, शहर के हर मोहल्ले के हर व्यक्ति, उसकी संपत्तियां जमीने, मकान, दुकान, बैंक खाता नं. जानने पर उस पर षड़यंत्रों के तहत देश की जनता को लूटने खोखला करने और एक रु. किलो का गेहूं-चावल खिलाकर जिंदा रखने की व्यवस्था की जा रही है। पूरे राष्ट्र की 125 करोड़ जनता का, देश के किस प्रदेश के किस शहर के किस गांव-मोहल्ले में किस स्तर के लोगों की आय, खान-पान, रहन-सहन का स्तर क्या है, ताकि विदेशी कंपनियां अमेरिका-इंग्लैंड में बैठकर तय कर सकें कि कहां से कितनी आय और लूट किये जाने के लिये न्यूनतम कितना धन, मानव श्रम और संसाधन उपयोग किये जाये इसके लिये समंक संकलन करने के लिये भारत के वित्त मंत्री, जो पूर्व में गृह मंत्री थे,ये ठेका हजारों करोड़ रु. में दिया गया जिसमें से रु. 700 करोड़ का ठेका जालसाज नंदन नीलकेणि को आधार कार्ड के लिये दे दिया गया ताकि वह डाटा दुनिया के बड़े पूंजीपतियों और उनकी बहुराष्ट्रीय कं. को उनके नियोजन और विनियोजन से कमाई का आधार तैयार कर सकें इस तथ्य को समय माया ने पूर्व में भी अपने प्रकाशनों में प्रस्तुत किया था। जिस पर सर्वोच्च न्यायालय ने भी उस टिप्पणी को आधार कार्ड पर लगाई गई याचिका के निर्णय में दोहराया था, कि आधार कार्ड का आधार क्या है। क्या केवल डाटा एकत्रित कर बहुराष्ट्रीय कं. को दिया जाना है, अब जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने समाचार पत्रों के अनुसार 30.6.14 तक किसी सार्वजनिक कार्यों में पहचान के रूप में अनिवार्य न किया जाये इसके विपरीत जबकि सरकार स्वयं मानती है कि अभी 20 प्रतिशत आबादी को ही सही कार्ड बनकर मिल सके है। पर सबसे आवश्यक वस्तु ईधन के रूप में गैस जो मात्र सरकारी कंपनियों के एकाधिकार में है जिसका दूसरा विकल्प नहीं है। साथ ही खुले बाजार में भी उपलब्ध नहीं है। इसलिये ये तीनों सरकारी कंपनियां इंडियन आइल, भारत और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम जिनके पास राष्ट्र के 25 करोड़ से ज्यादा ईधन गैस कनेक्शन धारियों को भरे सिलेंडर लेने से पहले लगातार एसएमएस संदेश भेजकर, समाचार पत्रों और समाचार की दूरदर्शनीय श्रंखलाओं व अन्य मनोरंजन श्रृंखलाओं से 31 दिस 13 की अंतिम तिथी बताकर लगातार धमका-चमका रही है। इससे गैस कनेक्शनधारी उपभोक्ताओं को न केवल आतंकित कर रही है। वरन सरकारी कं. होने के बाद भी सर्वोच्च न्यायालय को आदेश का अपमान करते हुए दिशा निर्देशों की धज्जियां भी बिखेर रही है। अन्यथा गैस न देने की सीधी धमकी दी जा रही है, दूसरी और जिन्होंने आधार कार्ड और बैंक खाता कं. दे दिया है, उन्हें वहीं गैस लगभग रु. 650 की पड़ रही है, जिसकी कीमत मात्र रु. 452 थी। इस आधार कार्ड के डाटा से नंदन नीलकेणी और उनकी कं. ने सरकार से मिले रु. 700 करोड़ के साथ ही न तो तरीके से आधार कार्ड ही बनाये है। जबकि आमजन ने तीन-तीन बार तक पंजीबद्ध होकर अपनी फोटो व अन्य जानकारी आधार कार्ड बनाने वालों को दी है। पर कईयों ने वर्ष भर बाद भी न तो आधार कार्ड मिले है, न उनके पास अन्य कोई जानकारी प्राप्त हुई है। 5 प्रतिशत कार्ड धारकों को कार्ड में दी गई जानकारी के अतिरिक्त नामों और पतों में अनेकों त्रुटियां की गई है। इसके विपरीत इस आधारभूत जनता की जानकारियां न केवल बहुराष्ट्रीय कं. के पास वरन चीन और पाकिस्तानके अनेकों संगठनों के हाथ भी लग चुकी है, जबकि कम्प्यूटर हैकरों की मानें तो नंदन नीलकेणी ने ही इस डाटा को दुनिया के अनेकों बहुराष्ट्रीय कं. को उपलब्ध करवाकर हजारों करोड़ रु. की ऊपरी कमाई तो कर ही ली है, साथ ही कंपनी में कार्यरत हर शहर में काम कर रही टीमों ने भी अपनी-अपनी पेन ड्राइव से डाटा चुराकर भी अदने से डाटा इंट्री आप्रेटरों ने भी नेताओं कं. व अन्य लाखों को डाटा बेंचकर भी अरबों रु. की बंदरबांट कर चुके है। दूसरी और आम रहवासियों को दो-दो तीन बार केन्द्रों पर जाने के बाद भी कार्ड मिल न मिले अपराधियों, जालसाजों, बांग्लादेशियों, पाकिस्तानी नागरिकों ने पैसे खर्च कर अलग-अलग स्थानों से आधार कार्ड बनवाकर दुरुपयोग करने की जानकारीयां भी चारों तरफ से प्राप्त हो रही है। जिस पर शासन की सुरक्षा का कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किया गया है। राष्ट्र की जनता की गोपनीय, सामाजिक, आर्थिक स्थितियों का इन कार्ड के डाटा से न केवल भारत की व्यायवसायिक कं. के साथ ही पूरी दुनिया की बहुराष्ट्रीय कं. और चीन-पाकिस्तान जैसे शत्रु राष्ट्रों की न केवल पहुंच में है वरन उसका वो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से लेकर अन्य अनेकों कार्यों में भी कर रहे है। जिस पर भारतीय सुरक्षा एजेंसियों का कोई नियंत्रण नहीं है, जो भारतीय सुरक्षा और अर्थ व्यवस्था के लिये भविष्य में भारी घातक होगा।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक- अजमेरा एस.पी. कुमार द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13 प्रेस कॉम्प्लेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 299, अम्बेडकर नगर, इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित।
भोपाल प्रतिनिधि- एस.के. भारद्वाज मो. 9074551045, इंदौर कार्यालय- 0731-2530859, मोबा. 9300755803